



04 - पाखंडी बाबाओं से मुक्ति की सार्थक पहल



05 - स्वच्छ भारत के नवरो में क्यों नजर नहीं आती स्लम बस्तियां?

A Daily News Magazine

इंदौर
शनिवार, 20 जुलाई, 2024



इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 9 अंक 269, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रु. 2 (डाक पंजीयन संख्या: MP/IDC/1529/2016-2018)



06- पुर्नवास प्रिया में पट्टेधारियों के साथ सरकारी जमीन पर दंगवाइयों का कब्जा



07- शासकीय संगीत महाविद्यालय धार में संगीत कार्यशाला में...



subahsaverenews@gmail.com



facebook.com/subahsaverenews



www.subahsavere.news



twitter.com/subahsaverenews

सुप्रभात

एक दिन आकाश से

गिरेंगे अंगारे

और सब कुछ भस्म

हो जाएगा

एक दिन नदी सूख जाएगी

पीने को पानी नहीं

मिलेगा

एक दिन हवा

जहरीली हो जायेगी

साँसें भी ज़हर उगलेंगी

एक दिन बाज़ार में

आदमी बिकने लगेगा

कुछ लोग खरीद लेंगे उन्हें

बहुत सस्ते में और

मौज करेंगे

एक दिन राजा का आदेश ही

कानून होगा

लोग सब उसके गुलाम होंगे ।

- दुर्गाप्रसाद झाला



प्रसंगवश

कमलेश पांडे

दुनिया के थानेदार अमेरिका ने तिब्बत के मसले पर चीन को जो दो टूक संदेश दिया है, उससे एक बार फिर वह चौखला उठा है और अमेरिकी नेतृत्व के प्रति अपनी आंखें तरेरीन शुरू कर दी है। उल्लेखनीय है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने तिब्बत-चीन विवाद के समाधान को बढ़ावा देने वाले 'रिजॉल्व तिब्बत एक्ट' पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। जिसमें तिब्बत पर चीन के अवैध कब्जे के शांतिपूर्ण समाधान के लिए दलाईलामा या उनके प्रतिनिधियों के साथ बिना शर्त सीधी बातचीत की बात कही गई है।

हालांकि, चीन ने इस एक्ट का विरोध करते हुए इसे अस्थिरता पैदा करने वाला बताया। उसने इस बिल पर अमेरिका से साफ शब्दों में कहा कि यह चीन के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप है। कोई भी व्यक्ति या ताकत, जो चीन को नियंत्रित करने के लिए या दबाने के लिए जिजांग (तिब्बत का चीनी नाम) को अस्थिर करने का प्रयास करेगी, सफल नहीं होगी। चीन अपनी संप्रभुता, सुरक्षा व विकास हितों की रक्षा के लिए कदम उठाएगा।

वहीं, इससे उलट निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रधानमंत्री सिक्चोंग पेप्मा सेरिंग ने रिजॉल्व तिब्बत एक्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन का आभार जताते हुए कहा कि यह कानून तिब्बती लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार की बात करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून में है। यह चीन के इस प्रचार व दावे को मंजूर नहीं करता कि तिब्बत कभी चीन का हिस्सा रहा है। यह धर्मगुरु दलाईलामा के आशीर्वाद से हो रहा है।

बता दें कि 1950 के दशक में चीन ने भारत की मूक सहमति से जब तिब्बत पर अपना कब्जा जमा

लिया तो वहां के सर्वोच्च धर्मगुरु यानी चौदहवें दलाईलामा 1959 में तिब्बत से भागकर भारत चले आये थे, जहां उन्होंने भारत सरकार से शरण मांगी और मिलने के बाद हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में अपनी निर्वासित सरकार स्थापित की। तभी से दलाईलामा से ज्यादा भारत चीन की आंखों में खटक रहा है। भारतीय प्रयासों के बाद 2002 से 2010 तक दलाई लामा के प्रतिनिधियों और चीनी सरकार के बीच नौ दौर की वार्ता हुई, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकला।

अलबत्ता, भारत इस मुद्दे पर भले ही शांत रहा, लेकिन उसके नए मित्र अमेरिका ने उसके दर्द को समझा और एशिया में अपनी राजनीति चमकाने और दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पर कब्जा जमाने की गरज से चीन के विरोध के बीच रिजॉल्व तिब्बत एक्ट को अमल में ला दिया। इससे पहले जम्मू-कश्मीर पर उसकी भूमिका से लगभग सभी वाकिफ हैं। इसलिए तो उसे दुनिया का थानेदार कहा जाता है। यह कटु सत्य है कि जिस काम को भारत और रूस को करना चाहिए, उसे करने का श्रेय भी अमेरिका ले चुका है।

गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने गत 12 जुलाई 2024 को तिब्बत सम्बन्धी विधेयक रिजॉल्व तिब्बत एक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसके बाद यह कानून बन गया है। यह प्रस्ताव तिब्बत के लिए अमेरिकी समर्थन बढ़ाने और इस हिमालयी क्षेत्र के दर्जे व शासन से सम्बन्धित विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए चीन और तिब्बत के सर्वोच्च धर्मगुरु दलाईलामा के बीच संवाद को बढ़ावा देने वाला है। बकौल बाइडन, मैं तिब्बतियों के मानवाधिकारों को बढ़ावा देने, उनकी विशिष्ट भाषाई, सांस्कृतिक व धार्मिक विरासत को संरक्षित करने के प्रयासों का समर्थन करने के लिए

संसद के दोनों सदनों की प्रतिबद्धता को साझा करता हूँ। मेरा प्रशासन चीन से दलाईलामा या उनके प्रतिनिधियों के साथ बिना किसी शर्त के सीधी बातचीत शुरू करने का आह्वान करता रहेगा, ताकि मतभेद दूर किये जा सकें और तिब्बत पर बातचीत के जरिए समझौता किया जा सके।

रिजॉल्व तिब्बत एक्ट में कहा गया है कि चीन की नीतियां तिब्बत के लोगों की जीवनशैली को संरक्षित करने की क्षमता को दबाने की कोशिश कर रही हैं। इसलिए यह कानून चीन के इस दावे को खारिज करता है कि तिब्बत प्राचीन काल से उसका हिस्सा रहा है। इस एक्ट में चीन से तिब्बत के इतिहास के बारे में गलत व भ्रामक प्रचार बन्द करने की मांग की है। यह कानून चीन के भ्रामक दावों से निपटने के लिए अमेरिका के विदेश विभाग को भी नए अधिकार देता है।

स्पष्ट है कि तिब्बत प्राचीन काल से चीन का नहीं, बल्कि भारत का पड़ोसी रहते हुए कभी कभार उसका अभिन्न अंग भी रहा है। पहले भारत के डाक वहां जाते थे और भारतीय मुद्रा भी वहां चलती थी। जब जब भारत के शासक कमजोर हुए तो तब तब वह स्वायत्त या स्वतंत्र देश बन गया। हालांकि आजादी के बाद पंचशील के सिद्धांतों का गला घोटते हुए चीन ने साल 1959 में जिस तरह से तिब्बत को जबरन अपने भूभाग में मिला लिया और तत्कालीन भारतीय नेतृत्व 'हिंदी-चीनी भाई-भाई' के गफलत में रहकर उसकी इस ओछी कार्रवाई का विरोध तक नहीं किया, वह एक अदूरदर्शी कदम साबित हुआ और उसकी कीमत आजतक भारत चुका रहा है।

अलबत्ता, अमेरिका के नए पैतरे से साफ है कि अंदरखाने में उसने भारत का विश्वास जरूर हासिल

किया होगा। क्योंकि चीन जिस तरह से भारत के अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा ठोकते हुए उसे दक्षिणी तिब्बत का भूभाग करार देता है, उसके परिप्रेक्ष्य में अमेरिकी कानून ने यह साफ कर दिया है कि जब तिब्बत ही चीन का हिस्सा नहीं है तो फिर भारतीय भूभाग पर उसका दावा वाकई फर्जी है।

वहीं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में चीनी हरकतें भी स्वीकार्य नहीं हो सकती हैं। नेपाल से लेकर भूटान की सीमा तक जो उसकी हरकतें हैं, उसके मद्देनजर रिजॉल्व तिब्बत एक्ट को चीनी चालों पर एक करारा तमाचा भी समझा जा सकता है, जो भारत ने अपने नए और रणनीतिक दोस्त से दिलवाई है। अब भी यदि चीन नहीं चेतेगा तो तिब्बत का उसके हाथ से फिसलना तय है।

अमेरिका ने जिस तरह से रूस को यूक्रेन में उलझाया, उसी तरह से अब वह चीन को तिब्बत में उलझायेगा। क्योंकि ताइवान और दक्षिण चीन सागर में चीन को घेरने से अच्छा है तिब्बत पर घेरेना, ताकि दो मोर्चे पर एक साथ उलझने की गलती वह कर बैठे। अब भारत को भी चाहिए कि चीनी विश्वासघात का बदला ले और तिब्बत मुक्ति संग्राम को शह प्रदान करके अपनी ऐतिहासिक भूल को सुधारे। स्पष्ट है कि रिजॉल्व तिब्बत एक्ट चीन के लिए एक खतरनाक पैगाम लेकर आया है। इसके कूटनीतिक मायने इस बात की चुगली कर रहे हैं कि पर्ल/रिंग पॉलिसी के माध्यम से भारत को घेरते रहने की अनवरत चाल चलते रहने वाला चीन अब खुद ही तिब्बत के मसले पर अमेरिकी जाल में फंसकर तड़फड़ने वाला है।

(प्रभासाक्षीफ डॉट कॉम पर प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

माइक्रोसॉफ्ट सर्वर डाउन से दुनियाभर में मची अफरा-तफरी

- भारत समेत एयरलाइन कंपनियों का कामकाज टप, चेक-इन भी प्रभावित
- दुनियाभर में 1 हजार प्लाइट कैंसिल
- बैंक, स्टॉक मार्केट और टीवी चैनल पर भी असर



नई दिल्ली (एजेंसी)। एंटीवायरस 'क्राइस्ट्राइक' के अपडेट से माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विसेज में शुक्रवार को दिक्कत आ गई। इसकी वजह से दुनियाभर में एयरलाइंस, टीवी टेलिक्रास्ट, बैंकिंग और कई कॉर्पोरेट कंपनियों के कामकाज पर असर पड़ा है। अमेरिका, ब्रिटेन और भारत जैसे कई देशों में 1 हजार से ज्यादा प्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। वहीं 3 हजार विमानों ने देरी से उड़ान भरी। भारत में, 5 एयरलाइन- इंडिगो, स्पाइसजेट, अकासा एयर, विस्तारा और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बताया कि उनकी बुकिंग, चेक-इन और प्लाइट अपडेट सर्विस इस तकनीकी समस्या से प्रभावित हुई है।



● क्राउडस्ट्राइक के अपडेट के कारण माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस टप हुई

दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के कुछ यूजर्स को अपने लैपटॉप पर नीली स्क्रीन दिखाई दे रही है। इससे उनके सिस्टम ऑटोमैटिकली रीस्टार्ट या शटडाउन हो गए हैं। डेल टेक्नोलॉजीज ने कहा कि यह समस्या हालिया क्राउडस्ट्राइक अपडेट के कारण हुई है। क्राउडस्ट्राइक एक साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को सिक्योरिटी सॉल्यूशन देता है। क्राउडस्ट्राइक के अपडेट के कारण ही माइक्रोसॉफ्ट के एज्योर क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्विसेज में परेशानी आई है।

स्पाइसेज ने कहा तकनीकी चुनौतियों का सामना कर रहे

स्पाइसेज ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है, वर्तमान में हम अपने सेवा प्रदाता के साथ तकनीकी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जिससे बुकिंग, चेक-इन और बुकिंग का प्रबंधन सहित ऑनलाइन सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। परिणामस्वरूप, हमने सभी हवाई अड्डों पर मैनुअल चेक-इन और



बोर्डिंग प्रक्रियाओं को सक्रिय कर दिया है। हम आगामी यात्रा योजना वाले यात्रियों से अनुरोध करते हैं कि वे हमारे काउंटरों पर चेक-इन पूरा करने के लिए सामान्य से पहले हवाई अड्डे पर पहुंचें। हम इसके कारण होने वाली किसी भी असुविधा के लिए ईमानदारी से खेद व्यक्त करते हैं और आपको आश्चस्त करते हैं कि हमारी टीमें इन मुद्दों को तुरंत हल करने के लिए हमारे सेवा प्रदाता के साथ लगन से काम कर रही हैं।

उ.प्र. में बाढ़, काशी में गंगा के 30 घाट डूबे

- गोरखपुर में एनडीआरएफ तैनात, मुंबई में 10 घंटे में 101मिमी बारिश; 13 राज्यों में अलर्ट,
- पोरबंदर में भारी बारिश के बाद बाढ़
- सुपौल में महादेव का मंदिर भी कोसी नदी में समाया

नई दिल्ली/लखनऊ/पटना (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगभग 1 हफ्ते से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर गोरखपुर में है। यहां राप्ती नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। अब तक 55 से ज्यादा गांव डूब चुके हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएससी की टीम 100 नावें लगाकर राहत-बचाव के काम में जुटी है।

गंगा नदी भी उफान पर गंगा नदी भी उफान पर है। वाराणसी में गंगा में 30 घाट डूब चुके हैं। दशाश्वमेध घाट के गंगा आरती स्थल तक पानी पहुंच गया है। अस्सी घाट की पुराने आरती स्थल की जगह बदल दी गई है। आज आरती 4 फीट पीछे होगी।



कर्नाटक में दीवार गिरने से तीन की मौत

उधर कर्नाटक में शुक्रवार सुबह भारी बारिश हुई। शिगांव के मदापुरा गांव में एक घर की दीवार गिरने से एक ही परिवार के 2 बच्चों समेत तीन लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने आज 13 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ हिंसा, 39 की मौत

प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियां फूँकी, सरकारी चैनल में आग लगाई; 300 लोग भारत पहुंचे

ढाका (एजेंसी)। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ हफ्ते भर से जारी विरोध-प्रदर्शन अब उग्र हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने गुरुवार शाम बांग्लादेश के मुख्य सरकारी टीवी चैनल बीटीवी के मुख्यालय में आग लगा दी। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक सैकड़ों प्रदर्शनकारी बीटीवी ऑफिस के कैम्पस में घुस आए और 60 से ज्यादा गाड़ियां फूँक दीं। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कल ही बीटीवी को इंटरव्यू दिया था। छात्रों और पुलिस के बीच हिंसक झड़पें भी हुईं। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा में 18 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा 2500 से अधिक लोग घायल हुए। बांग्लादेश में प्रदर्शन शुरू होने के बाद से कम से कम 39 लोगों की मौत हुई है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक लोक के निर्माण की समीक्षा

श्री रामराजा लोक ओरछा में भगवान श्रीराम के प्रसंगों को दर्शाया जाए : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल (नम्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि ओरछा में विकसित हो रहे श्री रामराजा लोक में भगवान श्रीराम के वनवास अवधि में वर्तमान मध्यप्रदेश के भू-भाग में बिताई गई समयावधि में हुए प्रमुख प्रसंगों को दर्शाया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक लोकों के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि इन स्थानों पर लाइट एंड साउंड शो की प्रस्तुति की व्यवस्था भी हो। प्रदेश में विकसित हो रहे विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक लोक के आय के साधन सुनिश्चित करते हुए उनके निर्माण और प्रबंधन प्रक्रिया तय की जाए, ताकि सभी लोकों का संचालन सुव्यवस्थित रूप से हो सके। लोकों का बेहतर प्रबंध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संबंधित विभागों जैसे संस्कृति, पर्यटन, धर्मस्व, राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा नगरीय विकास एवं आवास विभाग की स्थानीय स्तर पर संचालन समिति बनाई जाए। बैठक में संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास और धर्मस्व मंत्री श्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी, मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा, अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव संस्कृति तथा पर्यटन श्री शिवशेखर सुकुला तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।



भादवा माता लोक से आयुर्वेदिक अस्पताल को जोड़ा जाए

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सुनिश्चित करने को कहा कि विकसित हो रहे सभी धार्मिक और सांस्कृतिक लोकों के निर्माण कार्य में आकरष्यन इस प्रकार से हो कि सौंदर्यीकरण और आकर्षण दीर्घकालीन बना रहे। उन्होंने संत रविदास लोक, सागर में शोधपीठ और शैक्षणिक संस्था विकसित करने के निर्देश दिए। डॉ. यादव ने कहा कि भादवा माता लोक नीमच में श्रद्धालु दर्शन के साथ-साथ स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से भी आते हैं। भादवा माता लोक से आयुर्वेदिक अस्पताल और फिजियोथेरेपी सेंटर को भी जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मंदिर जिस स्थान पर शैली में बने हैं, उनकी विशेषताओं का संरचनाओं के निर्माण में अनुसरण सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के प्रचार-प्रसार के लिए प्रदेश की कला-संस्कृति-स्वास्थ्य और प्रमुख व्यंजनों पर केंद्रित मेले देश के अन्य राज्यों में आयोजित किए जाएं, इससे प्रदेश के पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

संक्षिप्त समाचार

संसद के बजट सत्र से पहले रणनीति बनाने में जुटा एनडीए, विपक्षी दलों को एक सुर में देगा जवाब

नई दिल्ली (एजेंसी)। संसद का आगामी बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू होने जा रहा है और इसके 12 अगस्त तक चलने की संभावना है। यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा संसद सत्र है और इसलिए केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा और केंद्र सरकार कई स्तरों पर इसे लेकर तैयारी कर रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के बाद राहुल गांधी ने पिछले सत्र के दौरान, जिस अंदाज में सरकार को घेरने की कोशिश की थी और जिस तरह से विपक्ष के कई राजनीतिक दल राहुल गांधी का साथ देते नजर आए। सरकार ने तैयार की काउंटर रणनीति- पिछले सत्र में विपक्ष के रवैये को देखते हुए भाजपा और सरकार ने सोमवार से शुरू होने जा रहे सत्र को लेकर काउंटर रणनीति तैयार कर ली है।

सीएम हिमंता बोले-

2041 तक मुस्लिम राज्य बन जाएगा असम

दिसपुर (एजेंसी)। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिरसा सरमा ने शुक्रवार (19 जुलाई) को कहा राज्य में मुस्लिम आबादी हर 10 साल में 30 प्रतिशत बढ़ रही है। ऐसे में साल 2041 तक



असम मुस्लिम बहुल राज्य बन जाएगा। यह हकीकत है और इसे कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा अगर राहुल गांधी जनसंख्या नियंत्रण के ब्रांड एंबेसडर बन जाते हैं तब इस पर नियंत्रण लग सकता है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय केवल उनकी बात सुनता है। असम सीएम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि डेमोग्राफिक डेटा के मुताबिक असम की मुस्लिम आबादी 40 फीसदी हो गई है। जबकि हिंदू समुदाय की आबादी हर 10 साल में करीब 16 फीसदी ही बढ़ रही है।

छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 2 आईडी ब्लास्ट...2 जवान शहीद, 6 घायल

बीजापुर/दंतेवाड़ा (एजेंसी)। दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिले की सीमा पर पिछले 24 घंटे में 2 अलग-अलग जगह आईडी ब्लास्ट हुए। जिसकी व्पोट में आने से



2 जवान शहीद हो गए, वहीं 6 जवान घायल हैं। घायलों में 2 डीआरजी के जवान हैं, बाकी एसटीएफ के हैं। इधर, दंतेवाड़ा पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में जवानों ने 1 महिला माओवादी को मार गिराया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि इन तीनों जिलों के बॉर्डर पर नक्सलियों के दरभ्रा डिवीजन, पश्चिम वस्तर डिवीजन और मिलिट्री नंबर 2 के नक्सली मौजूद हैं।

चिनाब ब्रिज पर 15 अगस्त को पहली ट्रेन चलेगी

यह दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज, 8 तीव्रता के भूकंप को झेल सकता है

श्रीनगर (एजेंसी)। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बने दुनिया के सबसे ऊंचे स्टील आर्च ब्रिज पर स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को पहली ट्रेन चलेगी। संगलदान से रियासी के बीच चलने वाली यह ट्रेन सर्विस उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है।

इस ब्रिज पर 20 जून को ट्रेन का ट्रायल रन हुआ था। इससे पहले 16 जून को ब्रिज पर इलेक्ट्रिक इंजन का ट्रायल हुआ था। यह ब्रिज पेरिस के एफिल टावर से 29 मीटर ऊंचा है। एफिल टॉवर की ऊंचाई 330 मीटर है, जबकि 1.3 किमी लंबे इस ब्रिज को चिनाब नदी पर 359 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है।

यह ब्रिज 40 किलो तक विस्फोटक और रिकटर स्केल पर 8 तीव्रता तक के भूकंप को झेल सकता है। पाकिस्तानी सीमा से इसका एरियल डिस्टेंस महज 65 किमी है। इस ब्रिज के शुरू होने से कश्मीर घाटी हर मौसम में ट्रेन के जरिए भारत के दूसरे हिस्सों से जुड़ जाएगी। यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट 1997 से शुरू हुआ था। इसके तहत 272 किमी की रेल लाइन बिछाई जानी थी। अब तक अलग-अलग फेज में 209 किमी लाइन बिछाई जा चुकी है। इस साल के अंत तक रियासी को कटरा से जोड़ने वाली आखिरी 17 किमी लाइन बिछाई जाएगी, जिसके बाद जम्मू के रियासी से कश्मीर के बारामूला तक पैसेंजर ट्रेवल कर सकेगा।



20 साल में बनकर तैयार हुआ ब्रिज

आजादी के 76 साल पूरे होने के बाद भी कश्मीर घाटी बर्फबारी के सीजन में देश के दूसरे हिस्सों से कट जाती थी। 22 फरवरी 2024 तक कश्मीर घाटी तक सिर्फ नेशनल हाईवे- 44 के जरिए जाया जा सकता था। बर्फबारी होने पर कश्मीर घाटी जाने वाला ये रास्ता भी बंद हो जाता था। इसके अलावा कश्मीर जाने के लिए जम्मू-तवी तक ही ट्रेन जाती थी, जहां से करीब 350 किलोमीटर लोगों को सड़क मार्ग से जाना पड़ता था। जवाहर टनल होते हुए गुजरने वाले इस रास्ते से लोगों को जम्मू-तवी से घाटी जाने के लिए 8 से 10 घंटे का समय लग जाता था। 2003 में भारत सरकार ने सभी मौसम में कश्मीर घाटी को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने के लिए चिनाब ब्रिज बनाने का फैसला लिया।

भारत स्वतंत्र हो गया, स्वाधीनता के लिए जारी है आंदोलन : यशवंत इंदपुरकर

हमें अकबर की वंशावली तो पढ़ाई, राम की नहीं, इस नैरेटिव के खिलाफ हमारी लड़ाई : अशोक श्रीवास्तव

भोपाल। भारत 1947 में स्वतंत्र हो गया, लेकिन उसे स्वाधीनता में बदलने का आंदोलन अभी चल रहा है। अंग्रेजों ने कुटिलतापूर्वक शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया और भारत को मानसिक गुलाम बना दिया। इससे उबरने का एक ही तरीका है- जनजागरण। यही कार्य देवर्षि नारद करते थे। यह बात विश्व संवाद केंद्र की ओर से आयोजित देवर्षि नारद जयंती समारोह एवं परिचर्चा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मध्य क्षेत्र कार्यकारिणी सदस्य यशवंत इंदपुरकर ने कही। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में दूरदर्शन के वरिष्ठ संपादक अशोक श्रीवास्तव उपस्थित थे। अध्यक्षता विश्व संवाद केंद्र न्यास के अध्यक्ष लक्ष्मेंद्र माहेश्वरी ने की। यह कार्यक्रम नर्मदासंगम रोड स्थित वृंदावन गार्डन के ‘समागम केंद्र’ में आयोजित हुआ। जिसमें भोपाल महानगर के पत्रकार, बुद्धिजीवी, मातृशक्ति, कला एवं सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े लोग शामिल हुए।

‘सांस्कृतिक पुनर्जागरण और मीडिया की भूमिका’ विषय पर श्री इंदपुरकर ने कहा कि डॉ. हेडगेवार जी ने 1911 में कहा था कि समाज में जागरूकता और प्रशिक्षण बेहद आवश्यक है। यह बात विख्यात कम्युनिस्ट नेता एमएन राय ने भी कही। सभी मनीषियों का मानना है कि जब तक संपूर्ण समाज नहीं बदलेगा, तब तक भारत के पुनरुत्थान का स्वप्न पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि देवर्षि नारद का नाम कलह कराने वाले के रूप में ही प्रचारित किया जाता रहा है। लेकिन उस विचार को बदलने का काम हम सबने किया है। कुछ वर्ष पहले जब मीडिया के साधियों के बीच हम देवर्षि नारद जयंती

मनाने के कार्यक्रम को लेकर जाते थे तो उपहास हुआ करता था। लेकिन वह धारणा बदली है और आज अधिकांश प्रतिष्ठित पत्रकारों की टेबल पर देवर्षि नारद की तस्वीर मिलती है, क्योंकि अब पत्रकारों ने अपने आद्य पुरुष को



पहचान लिया है। उन्होंने मान लिया है कि देवर्षि नारद विश्व के कल्याण के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे। जब हम सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात करते हैं तो हमें अपने आसपास घटित होने वाली सकारात्मक चीजों को भी देखना होगा। भारत के सांस्कृतिक उत्थान में मीडिया की बहुत प्रभावी भूमिका है। इस दायित्व को मीडिया के बंधुओं को पहचानना चाहिए।

इस अवसर पर प्रख्यात पत्रकार एवं डीडी न्यूज नई दिल्ली के संपादक अशोक श्रीवास्तव ने कहा कि हमें बचपन से पाठ्यक्रम में अकबर की वंशावली पढ़ाई गई लेकिन राम की नहीं। यह सब योजना पूर्वक किया गया। हमें किताबों में यह तो पढ़ाया गया कि अकबर महान थे। बाबर महान थे। प्राइमरी से हमें अकबर की वंशावली पढ़ाई गई, लेकिन राम की वंशावली नहीं पढ़ाई गई। इस प्रकार भारत की सांस्कृतिक विरासत को खत्म किया गया। हमारी लड़ाई इसी नैरेटिव

के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि मास मीडिया और बॉलीवुड ने देवर्षि नारद जी की तस्वीर चुगलखोर की बना दी थी। यह स्थिति आजादी के बाद से लगातार बनी है, क्योंकि बंटवारे के बाद पाकिस्तान ने खुद को इस्लामिक देश घोषित कर दिया और हमारे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की कहानी कही जाती रही। फिल्मों ने इसे मजबूत किया। फिल्मों में भारतीय संस्कृति के प्रतीकों को लंबे समय तक गलत ढंग से दिखाया। उसके कारण भारतीय संस्कृति के प्रति एक भ्रामक छवि युवाओं के मन में बन गई। उन्होंने राम मंदिर आंदोलन को पुनर्जागरण का सबसे बड़ा प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि आज पाठकों एवं दर्शकों के दबाव के कारण मीडिया रामलला का अखंड कवरेज दिखाता है। यह मीडिया का प्रायश्चित है, क्योंकि एक समय में मीडिया के एक हिस्से ने विवादित ढांचा गिराते समय कारसेवकों की छवि को सांप्रदायिक बताया था। यहां तक कि रामजन्म भूमि पर विवादित ढांचे को गिराने के बाद शौचालय बनाने की बात भी की गई थी। आज मीडिया ने अपना दृष्टिकोण बदला है क्योंकि समाज में अपनी संस्कृति के प्रति जागरूकता आयी है।

कार्यक्रम की प्रस्तावना केंद्र के न्यासी भावेश श्रीवास्तव ने रखी। कार्यक्रम के अंत में अध्यक्ष लक्ष्मेंद्र माहेश्वरी ने आभार ज्ञापन और संचालन वरिष्ठ पत्रकार डॉ. सुदीप शुक्ल ने किया। इस अवसर पर सरस्वती शिशु मंदिर, शिवजी नगर की छात्राओं ने देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी।

हरित संरक्षकों का होगा सम्मान

भोपाल। राजधानी के कुछ संगठनों ने मिलकर समाज सेवा की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए नया आयाम स्थापित किया है। गौरतलब है कि 20 जुलाई 2015 को अमेरिका के कैलीफोर्निया में सेनडियेगो शहर के महापौर ने म09प्र0 के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी श्री मनीष शंकर शर्मा के उत्कृष्ट सामाजिक योगदान और भारत अमेरिका संबंधों को प्रगाढ़ करने पर मनीष शंकर शर्मा दिवस उद्घोषित किया था जो कि पहली बार किसी भारतीय के नाम से अमेरिका में हुआ था। तभी से राजधानी में प्रतिवर्ष 20 जुलाई को इस दिवस पर सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

इसी कड़ी में और मध्यप्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले राज्य के गौरव श्री शर्मा से प्रेरणा लेते हुए अंतर्राष्ट्रीय संस्था लार्यंस क्लब, कैरियर समूह, आदि संगठनों ने प्रदेश के इतिहास में पहली बार (संभवतः भारत के इतिहास में भी) उन महानुभावों का सम्मान करने का निर्णय लिया है जो वाकई हमारे वृक्षों , पौधों और बागवानों का -24 घंटे, सातों दिन ,वर्ष भर - निरंतर संरक्षक करते हैं। हरित संरक्षक (माली बंधु) साथ ही में उन सुस्था संवर्धकों का भी सम्मान किया जायेगा जो इन बागवानों को सुरक्षित रखते हैं।

गांव में एक भी हेल्थ सेंटर मानक नहीं, सरकार से जवाब तलब

भोपाल। मध्यप्रदेश में बदहाल ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर हार्डकोट इंदौर ने प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। गांधीवादी विचारक एवं लेखक चिन्मय मिश्र ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में जनहित याचिका प्रस्तुत की थी। इसपर आज उच्च न्यायालय की युगल पीठ, जस्टिस एस.ए. धर्माधिकारी तथा जस्टिस दुष्यंक्ष वेंटक सम्रा ने नोटिस जारी कर मध्यप्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता चिन्मय मिश्र की ओर से अधिवक्ता अभिनव धनोङ्कर द्वारा पैरवी की गई थी।

याचिका के पक्ष में तर्क दिया गया कि स्वास्थ्य का अधिकार तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभ तथा पूर्ण उपलब्धता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन जीने के अधिकार की श्रेणी में आता है। यह एक मौलिक अधिकार है तथा सरकार का यह दायित्व है कि ग्रामीण इलाकों में व्याप्त बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में तुरंत सुधार करे।

याचिका का आधार यह है कि मध्यप्रदेश के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5 के अनुसार मध्यप्रदेश में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की नींव माना जाने वाला एक भी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राथमरी हेल्थ सेंटर या सब सेंटर भारत शासन के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के अनुसार कार्यरत नहीं हैं। इन

सेंटर्स में न तो उपयुक्त सुविधाएं हैं और न ही डॉक्टर तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध हैं।

उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं पर तथा महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। शिशु मृत्यु दर जहां सम्पूर्ण भारत में 32 प्रति 1000 है वहीं मध्य प्रदेश में यह 48 है। माताओं में मृत्यु दर सम्पूर्ण देश में 113 है वहीं मध्यप्रदेश में 173 है। साथ ही साथ ग्रामीण इलाकों में केवल 55 फीसदी महिलाओं की ही प्रसव के दौरान 4 बार देखरेख हो पाती है। जहां तक गर्भावस्था के समय में आयरन फोलिक एसिड हर गर्भवती महिला के लिए आवश्यक होता है लेकिन यह केवल 10 फीसदी गर्भवती महिलाओं को ही मिल पाता है। ग्रामीण प्रदेश की 70 फीसदी महिलाएं इससे वंचित रहती हैं, जिसका विपरीत प्रभाव उनपर तथा उनके होने वालों बच्चों पर पड़ता है। केवल 42 फीसदी महिलाओं द्वारा ही प्रसव के 1 घंटे के भीतर नवजात जो स्तनपान करवाया जाता है। मध्य प्रदेश में 58 फीसदी से अधिक महिलाएं खून की कमी से प्रभावित हैं।

2019-21 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5 के अनुसार मध्य प्रदेश में 309 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं, जिसमें हर एक सेंटर में एक फिजिशियन, एक सर्जन, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ तथा एक बच्चों के चिकित्सक की नियुक्ति होना आवश्यक है, परन्तु 309 में से

एक भी ऐसा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर नहीं है, जहां इस सब की नियुक्ति हो। कुल मिलाकर 324 सर्जन की नियुक्ति की आवश्यकता है, उनमें से केवल 7 की ही नियुक्ति हुई है और 302 पद खाली हैं। 324 जनरल फिजिशियन की नियुक्ति की आवश्यकता है, उनमें से केवल 7 की ही नियुक्ति हुई है और बाकी 302 पद खाली हैं। स्त्री रोग विशेषज्ञ में 324 में से केवल 21 पद भरे हैं बाकी 303 पद खाली हैं। बच्चों के विशेषज्ञों हेतु आवश्यकता 309 नियुक्तियों की है, परन्तु केवल 60 पद ही स्वीकृत हैं, जिनमें से भी केवल 11 पर ही नियुक्तियां हुई हैं। सबसे चौकाने वाले स्थिति यह है कि, मध्य प्रदेश में एक भी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में नेत्र रोग विशेषज्ञ नहीं है और केवल 5 ही एनेस्थेसिस्ट नियुक्त हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5 के अनुसार मध्य प्रदेश में 28 फीसदी सब सेंटर्स की कमी है, 47 फीसदी प्राथमरी हेल्थ सेंटर तथा 45 फीसदी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की कमी है। रिपोर्ट के अनुसार जितने भी सेंटर हैं, उनमें से एक भी सेंटर इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार कार्यरत नहीं है। हर सेंटर में कोई ना कोई कमी है जिसके कारण मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल स्थिति है, और इसका विपरीत प्रभाव सबसे अधिक महिलाओं और बच्चों पर पड़ रहा है।

एक भी ऐसा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर नहीं है, जहां इस सब की नियुक्ति हो। कुल मिलाकर 324 सर्जन की नियुक्ति की आवश्यकता है, उनमें से केवल 7 की ही नियुक्ति हुई है और 302 पद खाली हैं। 324 जनरल फिजिशियन की नियुक्ति की आवश्यकता है, उनमें से केवल 7 की ही नियुक्ति हुई है और बाकी 302 पद खाली हैं। स्त्री रोग विशेषज्ञ में 324 में से केवल 21 पद भरे हैं बाकी 303 पद खाली हैं। बच्चों के विशेषज्ञों हेतु आवश्यकता 309 नियुक्तियों की है, परन्तु केवल 60 पद ही स्वीकृत हैं, जिनमें से भी केवल 11 पर ही नियुक्तियां हुई हैं। सबसे चौकाने वाले स्थिति यह है कि, मध्य प्रदेश में एक भी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में नेत्र रोग विशेषज्ञ नहीं है और केवल 5 ही एनेस्थेसिस्ट नियुक्त हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5 के अनुसार मध्य प्रदेश में 28 फीसदी सब सेंटर्स की कमी है, 47 फीसदी प्राथमरी हेल्थ सेंटर तथा 45 फीसदी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की कमी है। रिपोर्ट के अनुसार जितने भी सेंटर हैं, उनमें से एक भी सेंटर इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार कार्यरत नहीं है। हर सेंटर में कोई ना कोई कमी है जिसके कारण मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल स्थिति है, और इसका विपरीत प्रभाव सबसे अधिक महिलाओं और बच्चों पर पड़ रहा है।

एक भी ऐसा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर नहीं है, जहां इस सब की नियुक्ति हो। कुल मिलाकर 324 सर्जन की नियुक्ति की आवश्यकता है, उनमें से केवल 7 की ही नियुक्ति हुई है और 302 पद खाली हैं। 324 जनरल फिजिशियन की नियुक्ति की आवश्यकता है, उनमें से केवल 7 की ही नियुक्ति हुई है और बाकी 302 पद खाली हैं। स्त्री रोग विशेषज्ञ में 324 में से केवल 21 पद भरे हैं बाकी 303 पद खाली हैं। बच्चों के विशेषज्ञों हेतु आवश्यकता 309 नियुक्तियों की है, परन्तु केवल 60 पद ही स्वीकृत हैं, जिनमें से भी केवल 11 पर ही नियुक्तियां हुई हैं। सबसे चौकाने वाले स्थिति यह है कि, मध्य प्रदेश में एक भी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में नेत्र रोग विशेषज्ञ नहीं है और केवल 5 ही एनेस्थेसिस्ट नियुक्त हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5 के अनुसार मध्य प्रदेश में 28 फीसदी सब सेंटर्स की कमी है, 47 फीसदी प्राथमरी हेल्थ सेंटर तथा 45 फीसदी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की कमी है। रिपोर्ट के अनुसार जितने भी सेंटर हैं, उनमें से एक भी सेंटर इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार कार्यरत नहीं है। हर सेंटर में कोई ना कोई कमी है जिसके कारण मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल स्थिति है, और इसका विपरीत प्रभाव सबसे अधिक महिलाओं और बच्चों पर पड़ रहा है।

एक भी ऐसा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर नहीं है, जहां इस सब की नियुक्ति हो। कुल मिलाकर 324 सर्जन की नियुक्ति की आवश्यकता है, उनमें से केवल 7 की ही नियुक्ति हुई है और 302 पद खाली हैं। 324 जनरल फिजिशियन की नियुक्ति की आवश्यकता है, उनमें से केवल 7 की ही नियुक्ति हुई है और बाकी 302 पद खाली हैं। स्त्री रोग विशेषज्ञ में 324 में से केवल 21 पद भरे हैं बाकी 303 पद खाली हैं। बच्चों के विशेषज्ञों हेतु आवश्यकता 309 नियुक्तियों की है, परन्तु केवल 60 पद ही स्वीकृत हैं, जिनमें से भी केवल 11 पर ही नियुक्तियां हुई हैं। सबसे चौकाने वाले स्थिति यह है कि, मध्य प्रदेश में एक भी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में नेत्र रोग विशेषज्ञ नहीं है और केवल 5 ही एनेस्थेसिस्ट नियुक्त हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5 के अनुसार मध्य प्रदेश में 28 फीसदी सब सेंटर्स की कमी है, 47 फीसदी प्राथमरी हेल्थ सेंटर तथा 45 फीसदी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की कमी है। रिपोर्ट के अनुसार जितने भी सेंटर हैं, उनमें से एक भी सेंटर इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार कार्यरत नहीं है। हर सेंटर में कोई ना कोई कमी है जिसके कारण मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल स्थिति है, और इसका विपरीत प्रभाव सबसे अधिक महिलाओं और बच्चों पर पड़ रहा है।

रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के कृषि संकाय द्वारा हाईटेक कस्टम हायरिंग सेंटर का उद्घाटन कार्यक्रम संपन्न

भोपाल। रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के कृषि विभाग द्वारा हाईटेक कस्टम हायरिंग सेंटर का उद्घाटन कार्यक्रम हुआ। जिसमें बतौर मुख्य अतिथि श्री बी. एस. कोठारी, असिस्टेंट इंजीनियर भोपाल संभाग, कृषि अभियांत्रिकी, मध्य प्रदेश शासन, आरएनटीयू के कुलाधिपति श्री संतोष चौबे, कुलसचिव डॉ विजय सिंह एवं उपकुलपति

चाहिए और अपने विश्वविद्यालय के कृषि छात्रों को गाँव में किसानों के खेतों पर भी जाने की सलाह दी। इस उपरांत डॉ. विजय सिंह द्वारा कस्टम हायरिंग के महत्व को बताते हुए कृषकों को संबोधित किया एवं विभाग को शुभकामनाएं दी।

इस मौके पर विश्वविद्यालय के कृषि विभाग के डीन डॉ. एच. डी. वर्मा ने कार्यक्रम की रूपरेखा



डॉ संगीता जौहरी मुख्य रूप से उपस्थित थे। अतिथियों ने रिबन काटकर केंद्र का उद्घाटन किया।

इस मौके पर श्री बी. एस. कोठारी जी ने विभाग की योजनाओं के बारे में कृषकों को अवगत करते हुए कृषि यांत्रिकी के द्वारा किये गए कार्य को जिला व राज्य स्तर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किस प्रकार किसान योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। वहीं श्री संतोष चौबे जी ने कहा की अब खेती की पुरानी विधियों को छोड़ कर उजत कृषि यंत्रों एवं तकनीकियों को अपना कर नयी विधियों की ओर अग्रसर होना होगा। साथ ही जैविक खेती को बढ़ावा देकर कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन करना होगा। उन्होंने यह भी कहा की किसान भाइयों को कस्टम हायरिंग एवं कृषि की अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ लेना

रखी। हाईटेक कस्टम हायरिंग केंद्र के समन्वयक डॉ. अशोक कुमार वर्मा ने केंद्र के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में सभी कृषि उपकरणों का अतिथियों द्वारा पूजन एवं निरीक्षण किया गया। वहीं अतिथियों द्वारा हाईटेक कस्टम हायरिंग सेंटर, कृषि परामर्श केंद्र एवं देसी कार्यक्रम से सम्बंधित कृषि साहित्य का विमोचन किया, किसानो को बीज के मिनी किट दिए एवं उन्हें सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के अंगीकृत गांवों से लगभग 65 किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन एवं कार्यक्रम की भूमिका डॉ. ऋषिकेश मंडलोई, सहायक प्राध्यापक द्वारा की गई। आभार प्रदर्शन डॉ. शुभम कुलश्रेष्ठ, सहायक प्राध्यापक ने दिया। इस मौके पर विश्वविद्यालय के विद्यार्थी फैकल्टी सहित कृषि विभाग के सभी सदस्य विशेष रूप से उपस्थित थे।

इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट में 22 जुलाई को सुनवाई

नई दिल्ली (एजेंसी)। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एनजीओ कॉमन कोज और सेंटर फॉर पब्लिक इंटररेस्ट लिटिगेशन ने बॉन्ड के लेनदेन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग की है। इस पर 22 जुलाई को सुनवाई होगी। सुनवाई सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच करेगी।

गुजरात में वलसाड और सूरत स्टेशन के बीच मालगाड़ी पटरी से उतरी, रेल सेवाएं प्रभावित

अहमदाबाद (एजेंसी)। गुजरात में वलसाड और सूरत स्टेशनों के बीच शुक्रवार को एक मालगाड़ी की डिब्बा पटरी से उतर गया। हालांकि इस दौरान किसी के घायल होने की खबर नहीं है। पश्चिमी रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि दोपहर करीब 3 बजे डुमरी स्टेशन के पास हुई इस घटना के कारण मार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ। मालगाड़ी सूरत की तरफ जा रही थी।

78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम होगी- विकसित भारत



मुंबई (एजेंसी)। मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने 10 करोड़ की कीमत वाले 5 किलोग्राम मेफेड्रोन ड्रग्स के साथ एम एस शेख नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। एनसीबी के अधिकारी ने बताया कि ड्रग्स के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। आरोपी ने मुंबई में ड्रग्स सप्लाई करने के लिए हैदराबाद से मंगवाया था। शेख मेफेड्रोन की इंटर स्टेट तस्करी गैंग में शामिल है।

कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार का बड़ा आदेश

‘हर दुकान पर नेम प्लेट लगाएं दुकानदार’

● प्रियंका गांधी ने कहा-यह लोकतंत्र पर हमला; मुस्लिम जमात फैसले के समर्थन में

लखनऊ (एजेंसी)। यूपी में कांवड़ यात्रा मार्गों पर पड़ने वाली दुकानों में दुकानदार को अपना नाम लिखना होगा। इसमें दुकान मालिक का नाम और डिटेल लिखी जाएगी। शुक्रवार को सीएम योगी ने यह आदेश दिया। सरकार का कहना है कि कांवड़ यात्रियों की सुविधा बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया है। इसके अलावा, हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। यूपी के बाद उत्तराखंड के हरिद्वार में भी यह आदेश लागू कर दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने इस फैसले को असंवैधानिक बताया। कहा- यह फैसला



चुनावी लाभ के लिए है। एडीजी बोले- यह नया आदेश नहीं-मेरठ जोन एडीजी डीके ठाकुर ने कहा- यह कोई नया आदेश नहीं है। इसका पिछले साल भी पालन कराया गया था। आदेश को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति उत्पन्न की गई है। जाति-धर्म के नाम पर विभाजन का समर्थन नहीं- चिराग पासवान-केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि वह जाति या धर्म के नाम पर किसी भी विभाजन का समर्थन नहीं करते हैं। उन्होंने मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा जारी गाइडलाइंस का विरोध करते हुए कहा कि मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं।

निलंबित हॉस्टल वार्डन की कार में मिली शराब

इंदौर (एजेंसी)। इंदौर में चोरल के आदिवासी कन्या छात्रावास की वार्डन शिल्पा गौड़ शिकायत के बाद निलंबित हो चुकी है। छात्राओं ने जिला प्रशासन से शिकायत में कहा था कि पूर्व सरपंच का गर्लस हॉस्टल में आना जाना था। जब वार्डन को शो-काॅज नोटिस जारी किया गया तो कारवाई से बचने के लिए उसने विभाग को भी गुमराह किया। 17 जुलाई को पूर्व सरपंच और वार्डन का एक वीडियो सामने आया। इसमें पूर्व सरपंच को पत्नी वार्डन पर आरोप लगाते दिख रही है। वीडियो 9 जुलाई का हॉस्टल के बाहर का है। पूर्व सरपंच की पत्नी का आरोप है कि वार्डन ने उसके परिवार को तबाह कर दिया। उसका पति से अफेयर है। पूर्व सरपंच के हॉस्टल में आने-जाने और वीडियो को लेकर वार्डन ने विभाग को जवाब दिया - पूर्व सरपंच हॉस्टल से मेरा टैबलेट ले गया था। उसे वापस लेने के लिए मैं उसके पीछे गई। हॉस्टल के बाहर उसकी पत्नी पहले से मौजूद थी। टैबलेट लेने की बात पर उन्होंने हंगामा कर दिया।पूर्व सरपंच का कहना है कि वो पत्नी के साथ कार से जा रहा था। वार्डन ने लिफ्ट मांगी थी। कोई टैबलेट नहीं छीना था। पूर्व सरपंच ने ये भी बताया कि वार्डन हॉस्टल में शराब रखती है। एक बार इसकी कार में बैठा था, तब शराब के क्रांटर मिले थे। पूछने पर उसने कहा था- मुझे रोज लगती है। हॉस्टल में पीती हूं।

छात्राओं ने वार्डन की शिकायत में क्या बताया...

16 जुलाई को दो छात्राओं ने जिला प्रशासन से वार्डन शिल्पा गौड़ की शिकायत

पूर्व सरपंच से बोली- मुझे रोज लगती है; छात्राओं ने की थी बाहरी पुरुष बुलाने की शिकायत



की। इसमें कहा कि शिल्पा पुरुषों को हॉस्टल बुलाती है। सीसीटीवी कैमरे बंद कर देती है। पुरुष यहां शराब पीते हैं। डीजे बजता है। हॉस्टल में खाना बनाने वाले कर्मचारियों पर बाहर के पुरुषों को खाना खिलाने का दबाव बनाती है। ड्राइवर सलमान हॉस्टल में घूमता रहता था। बिना अनुमति बच्चियों को बाहर ले जाती है। छात्राओं ने बच्चियों को खाने में नशीला पदार्थ देने और अन्य पुरुषों के साथ जबरदस्ती खाना खाने का दबाव बनाने के आरोप भी लगाए।

एक छात्रा ने बताया, एक साल पहले प्रिंसपल से वार्डन की शिकायत की थी। इस पर उसने धमकाया। हॉस्टल में एक लड़की के पास मोबाइल मिला था। बदला लेने के लिए वार्डन हमारा नाम लगाकर हॉस्टल से निकलवा दिया। गलती एक लड़की की थी और 5 लड़कियों को निकाल दिया था। छात्रा ने बताया, अब हमें घर से स्कूल जाना पड़ता है। स्कूल सुबह 10.30 बजे से लगता है।

पूर्व सरपंच की पत्नी बोली - शिल्पा ने मेरा परिवार तबाह किया, इसे नौकरी से निकालो

पूर्व सरपंच नारायण पटेल की पत्नी ने बताया, करीब 5-6 साल पहले शिल्पा और मेरे पति की पहचान हुई थी। पति तब सरपंच थे। शिल्पा के पिता का निधन हो गया था। मेरे पति ने उसकी मदद की थी, लेकिन इसने मेरा घर ही तबाह कर दिया। पति को फंसा लिया। कई बार समझाने पर भी नहीं मानी। लॉकडाउन में पति को अपने साथ रख लिया।पति को जब कोरोना हुआ तो भगा दिया। मैंने पति का इलाज करवाया। लॉकडाउन खत्म हुआ तो फिर उन्हें बुलाने लगी। शराबखोरी करती। हॉस्टल में पार्टी करती। परेशान होकर मैंने विधायक उषा दीदी से शिल्पा की शिकायत की। इसके बाद उसका हातोद में ट्रांसफर हो गया। घर में शांति हो गई थी। सब कुछ अच्छ चल रहा था। मैं, मेरी बेटी और पति सब अच्छे से रह रहे थे। कुछ ही महीने बाद शिल्पा वापस हातोद से ट्रांसफर करवाकर चोरल आ गई। दोबारा पति को फंसा लिया। 9 जुलाई को मैंने दोनों को कार में रंगे हाथों पकड़ा। शिल्पा की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसके बाद उसने पति पर ही झूठा केस दर्ज करवा दिया। हॉस्टल में लड़कियां भी इससे परेशान हैं। विभाग ने शिल्पा को निलंबित किया है, लेकिन इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसे नौकरी से निकाला जाए।

सुबह 8 बजे घर से निकलना पड़ता है। दो बार बस बदलनी पड़ी। घर आते-आते शाम के 6 बज जाते हैं। हॉस्टल में थे तो सड़क पार करते ही सामने स्कूल था। वार्डन मैम के कारण पढ़ाई प्रभावित हो रही है।

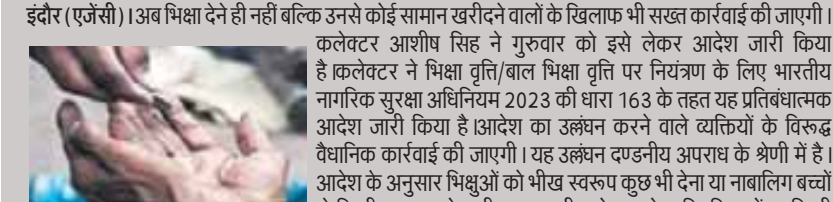
पूर्व सरपंच नारायण पटेल ने कहा- मदद की, मुझे ही झूठा फंसाया

पूर्व सरपंच ने कहा, शिल्पा का जब हातोद ट्रांसफर हुआ था, तब मैं एक बार इसकी कार में बैठा था। गाड़ी में शराब के क्रांटर रखे थे। पूछने पर शिल्पा कहने लगी- मुझे तो लगती है। घर और हॉस्टल में भी

रखती हूं। मैंने पूछा कि कौन लाकर देता है। तो बोली कि ड्राइवर सलमान लाकर देता है।9 जुलाई को भी मैं हॉस्टल नहीं गया था। मैं कार से जा रहा था, तब शिल्पा रास्ते में खड़ी मिली। उसने लिफ्ट मांगी। रास्ते में पत्नी और बेटी दिखी तो गाड़ी रोकी। ड्राइवर हुआ और शिल्पा ने मेरी झूठी रिपोर्ट दर्ज करवा दी। मैंने इसका टैबलेट नहीं छीना।मैं शिल्पा को 5-6 साल से जानता हूं। तब सरपंच था। शिल्पा ने किसी से मेरा नंबर लेकर फोन कर मदद मांगी थी। पिता के स्थान पर शिल्पा की अनुकंपा नियुक्ति लगी थी। स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन परमानेंट नहीं थी।

अब भीख देने वालों पर भी होगी कार्रवाई

नाबालिग को भिक्षा देना या उनसे सामान खरीदना भी अपराध; कलेक्टर ने जारी किया आदेश



इंदौर (एजेंसी)।अब भिक्षा देने ही नहीं बल्कि उनसे कोई सामान खरीदने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर आशीष सिंह ने गुरुवार को इसे लेकर आदेश जारी किया है। कलेक्टर ने भिक्षा वृत्ति/बाल भिक्षा वृत्ति पर नियंत्रण के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यह उल्लंघन दण्डनीय अपराध के श्रेणी में है। आदेश के अनुसार भिक्षुओं को भीख स्वरूप कुछ भी देना या नाबालिग बच्चों से किसी सामान को खरीदना दण्डनीय होगा। जो व्यक्ति भिक्षुओं या किसी नाबालिग बच्चे को भीख स्वरूप कोई चीज प्रदान करता है या नाबालिग बच्चे से कोई सामान खरीदता है तो उसके कार्रवाई होगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और 14 सितम्बर 2024 तक प्रभावशील रहेगा। दरअसल इंदौर में ट्रैफिक सिग्नल, चौराहों, धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और अन्य सार्वजनिक स्थानों में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे स्वयं या अपने परिवारों के साथ भिक्षा वृत्ति में लिस दे रहे गए हैं। इसमें अन्य शहरों के बच्चे भी होते हैं। अधिकांश बच्चे नश्वर या अन्य गतिविधियों में भी लिस होते हैं। इसी तरह बाल भिक्षा वृत्ति कराने के लिए बच्चों की तस्करी के मामले संज्ञान में आये हैं। बच्चों के ट्रैफिक सिग्नल पर भिक्षा वृत्ति के कारण घट्पटना होने की आशंका के साथ यह एक सामाजिक बुराई है। भिक्षा वृत्ति और बाल भिक्षा वृत्ति को रोकने के लिए विभिन्न विभागों के सात टीम बनाई गई है।

पातालपानी-कालाकुंड हेरिटेज ट्रेन की बुकिंग आज से

इंदौर में 10 किमी के ट्रैक पर झरने-वादियों का नजारा, 5 कोच के साथ हफ्ते में दो दिन चलेगी

इंदौर (एजेंसी)। मध्य प्रदेश की इकलौती पातालपानी-कालाकुंड हेरिटेज ट्रेन शनिवार से शुरू होगी। पर्यटकों की डिमांड के बाद रेलवे ने गुरुवार देर शाम हेरिटेज ट्रेन के शुरू होने की जानकारी दी। इसकी बुकिंग शुक्रवार से शुरू होगी। 20 जुलाई से शुरू हो रही हेरिटेज ट्रेन सप्ताह में दो दिन यानी प्रति शनिवार एवं रविवार को चलेगी। संचालन से पहले हेरिटेज ट्रेन पावर कार मटेनेंस के बाद मह स्टेशन आ चुकी है। इसके साथ ही पातालपानी, टंटया भील, व्यू पाइंट, कालाकुंड स्टेशन का और बेहतर कर दिया गया है। ट्रेन शनिवार सुबह 11.05 बजे पातालपानी से कालाकुंड के लिए रवाना होगी। जिसे सांसद लालवानी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार ट्रेन पातालपानी से कालाकुंड के बीच 10 किमी ट्रैक पर चलेगी। इस ट्रैक पर सफर के दौरान यात्री पातालपानी स्टेशन, पातालपानी वाटर फॉल, वैली ब्रिज, कालाकुंड और टनल के रोमांच का लुफ्त उठाएंगे।पातालपानी से कालाकुंड के बीच पर्यटक ऐसे कई झरनों का लुफ्त उठा सकेंगे।
बुकिंग शुरू - रेलवे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रात में पातालपानी-कालाकुंड के बीच हेरिटेज ट्रेन दो विस्टाडोम



सी-1 और सी-2 (एसी चेयर-कार) कोच और तीन नॉन एसीडी1, डी-2 और डी-3 कोच के साथ चलेगी। हेरिटेज ट्रेन में आने-जाने का अलग-अलग टिकट लेना होगा।विस्टाडोम के एक कोच में 60 सीट है। इसमें एसीचेयर-कार का 265 रुपए, जबकि नॉन एसी चेयर-कार का क्रियाया 20 रुपए प्रति टिकट रह सकता है। नॉन एसी चेयर-कार के तीन कोच हैं। ट्रेन संख्या 52965/52966 पातालपानी- कालाकुंड हेरिटेज ट्रेन में टिकट की बुकिंग सभी पीआरएस काउंटेंटों, आईआरसीटीसी की वेबसाइट से ऑनलाइन या रिजर्वेशन सेंटर से की जा सकती है।

इंदौर से ऐसे पहुंच सकते हैं ट्रेन तक

रेलवे इंदौर से मह और पातालपानी तक हेरिटेज ट्रेन में ले जाने के लिए डेम्प चालाने का निर्णय कर रहा है। हालांकि रेलवे सूत्रों का कहना है कि शुक्रात में कुछ दिन यात्रियों को

पातालपानी तक सड़क मार्ग से ही जाना पड़ेगा। हालांकि रेलवे महू से पातालपानी तक ब्राइज पर रेल लाइन का निरीक्षण कर चुका है। एक दो दिन में रतलाम से होकर महू जाने वाली डेम्प ट्रेन 09390 को पातालपानी तक विस्तार किया जा सकता है। जिसके बाद रेल यात्री इंदौर और महू रेलवे स्टेशन से सीधे ट्रेन द्वारा की पातालपानी रेलवे स्टेशन पहुंच सकेंगे।

इस समय पर चलेगी ट्रेन

ट्रेन संख्या 52965 पातालपानी कालाकुंड हेरिटेज ट्रेन 11.05 बजे पातालपानी से चल कर 13.05 बजे कालाकुंड पहुंचेगी। वहीं वापसी ट्रेन संख्या 52966 कालाकुंड पातालपानी हेरिटेज ट्रेन कालाकुंड से 15.34 बजे चल कर 16.30 बजे पातालपानी पहुंचेगी। हेरिटेज ट्रेन पातालपानी से कालाकुंड 2 घंटे में पहुंचती है। वापसी में काला कुंड से पातालपानी तक आने में ट्रेन को एक घंटा लगता है। ट्रेन काला कुंड पहुंचने के बाद वहां लोगों को घूमने के दौरान करीब दो घंटा खड़ी रहेगी। इस दौरान यात्री कालाकुंड के झरने और पहाड़ों की सैर कर सकेंगे।

2018 में हुई थी शुक्रात- पातालपानी से कालाकुंड की वादियों के ट्रैक को 2018 में हेरिटेज ट्रैक घोषित किया गया था। इसी के साथ प्रदेश की एकमात्र हेरिटेज ट्रेन की शुक्रात हुई थी।

इंदौर में कार मालिक से हेराफेरी किराए का एग्रीमेंट करने के बाद महाराष्ट्र भेज दी कार, ना किराया दिया, ना कार लौटाई

इंदौर (एजेंसी)। इंदौर के बाणगंगा में कार मालिक से हेराफेरी का मामला सामने आया है। इसमें एक व्यक्ति ने कार का एग्रीमेंट कर उसे किराए पर लिया और ड्राइवर को सौंप दी। वह कार को महाराष्ट्र ले गया और वापस ही नहीं की। पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को आरोपी बनाया है। बाणगंगा पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मुकेश पुत्र लक्ष्मी नारायण परमार निवासी महेश यादव नगर की शिकायत पर पुलिस ने सचिन पुत्र दिनेश कौशल, निवासी मुखर्जी नगर और उसके ड्राइवर राजनंद उर्फ शुभम पुत्र महादेव रेवास्कर, निवासी बुलडाणा महाराष्ट्र के खिलाफ केस दर्ज किया है।मुकेश ने बताया कि उसका और सचिन का अटीगा कार को लेकर 22 मार्च 2024 को एग्रीमेंट हुआ था। जिसमें 25,500 रुपए मासिक किराया तय हुआ। 2 माह तक सचिन ने किराया दिया। लेकिन फिर किराया नहीं आया। तो उससे पूछा कि कार कहाँ है, किराया क्यों नहीं दे रहे। तब सचिन ने कहा कि कार ड्राइवर राजनंद के पास है। वह कार लेकर महाराष्ट्र से नहीं आया। इसके बाद कई बार पूछने के बाद सचिन ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया।

खजराना-वजन तोलने वाले ने की हरकत

शौचालय की खिड़की से नवविवाहिता का वीडियो बनाया, पीड़िता पुलिस के पास पहुंची

इंदौर (एजेंसी)। इंदौर के खजराना मंदिर परिसर में एक नव विवाहिता का अश्लील वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। गार्ड के पहचानने के बाद पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज किया है। आरोपी मंदिर परिसर में ही आता-जाता है। पुलिस अब आगे मामले में जांच कर रही है।खजराना पुलिस में बताया आरोपी संजू निगवाल की शिकायत मिली है। देवास से आई 24 साल की युवती ने उसकी शिकायत की है। शिकायत में बताया गया है कि संजू बाथरूम की खिड़की से झांक रहा था। वहां महिला का वीडियो बना लिया। महिला ने शौचालय से बाहर आकर पति को जानकारी दी। पति ने उसका पीछा किया लेकिन वह भाग निकला। इसके बाद दंपती ने गार्ड से शिकायत की। उन्होंने कंट्रोल रूम में जाकर देखा तो आरोपी की पहचान हो गई। गार्ड ने बताया कि आरोपी संजू निगवाल मंदिर परिसर में वजन तोलने की मशीन लेकर बैठता है।गार्ड द्वारा पहचान होने के बाद आरोपी पर पीड़िता ने खजराना थाने जाकर उस पर केस दर्ज कराया है।

इंदौर में हुई बीजेपी नगर कार्यसमिति की बैठक

संभागीय प्रभारी गौतम बोले- इंदौर देश को प्रेरणा देने वाला शहर, ताई ने कहा,भाजपा का कार्यकर्ता हमेशा जीतेगा

इंदौर (एजेंसी)। इंदौर में आज बीजेपी नगर कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया था। जिसमें पूर्व सांसद और लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, विधायक गोतू शुक्ला, विधायक रमेश मंदोला, विधायक मधु चर्मा और विधायक महेंद्र हार्डिया के साथ अन्य नेता और पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि जब हम सत्ता में रहते हैं तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। इस हेतु हमें जिन कार्यों के लिए जनता ने वोट दिया है, वह कार्य अच्छी तरह से जनता के बीच पहुंच रहे हैं या नहीं, योजनाओं का लाभ जनता को ठीक तरीके से मिल रहा है या नहीं, इसकी चिंता कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से करनी चाहिए।

भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने कार्यों से हमेशा जीतता रहेगा, मेरा आशीर्वाद हमेशा कार्यकर्ताओं के साथ रहता है। बैठक में संभाग प्रभारी राघवेंद्र गौतम ने कहा कि हमें जनता ने अभूतपूर्व सहयोग प्रदान किया है, जिसके कारण हमारी जिम्मेदारी पहले से ज्यादा बढ़ जाती है। हमें शहर के सामाजिक एवं विकास कार्यों में टीम वर्क के साथ काम करते हुए एक दूसरे को सहयोग करना है। हम दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं अटल बिहारी वाजपेयी जी की पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम जिस भी क्षेत्र में कार्य करते हैं, उस क्षेत्र में हमारी पार्टी की पहचान को बनाए रखने एवं आगे बढ़ाने की हम सभी की जिम्मेदारी है। इंदौर शहर पूरे देश को प्रेरणा देने वाला शहर है। इंदौर शहर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का केंद्र बिंदु है। यहां से जो भी बात



निकलती है, उसका असर पूरे देश पर पड़ता है। इस हेतु हमें सामाजिक सरोकार के कार्यों को भी पूर्ण निष्ठा से करना है। बैठक में नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे ने कहा कि इंदौर ने कार्यकर्ताओं के परिश्रम से इतिहास रचने का काम किया है। लोकसभा चुनावों में विपक्ष के नेताओं ने नोटा के लिए माहौल बनाने का प्रयास किया, लेकिन वे विफल रहे और भारतीय जनता पार्टी ने सामूहिक प्रयास से पूरे देश में सर्वाधिक मतों से इंदौर में विजय प्राप्त की है। इसमें बहुत बड़ी भूमिका शक्ति केंद्र एवं बुध के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की हमारी केंद्र एवं प्रदेश की योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक ले जाने का काम किया। वोटर लिस्ट में से फर्जी नाम हटाकर सही नाम जोड़ने के साथ ही नए वोटर के नाम जुड़वा कर कार्यकर्ताओं ने बहुत पहले ही चुनाव की योजना

की तैयारी प्रारंभ कर ली थी। बैठक को संबोधित करते हुए सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि 10 वर्षों कि माननीय मोदी जी की सरकार ने अनेक कार्य किए, पिछले वर्षों में इंदौर में ही गरीब कल्याण के अनेक कार्य जिसमें निशुल्क अन्न देना हो या आयुष्मान योजना जिसमें इंदौर देश में नंबर वन है ,इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा घर देना हो या नल जल योजना के माध्यम से घर घर जल पहुंचाने का कार्य करना हो या फिर उज्ज्वला योजना के माध्यम से सभी घर में रसोई गैस पहुंचना हो या किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को राहत पहुंचानी हो ऐसे आने को कार्य किए हैं इसके साथ ही इंदौर की अनेकविविधि भी देश के महत्वपूर्ण शहरों से सड़क, रेल एवं वायु मार्ग के माध्यम से आगामी 2 वर्षों में बहुत बेहतर होने जा रही है।

जनहित याचिका पर इंदौर हाई कोर्ट ने 4 सप्ताह में मांगा जवाब, अगली सुनवाई 20 अगस्त को



धड़झले से काटने का कार्य कर रहे हैं।याचिकाकर्ता द्वारा अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत वर्णित प्रक्रिया को भी याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई। धारा 6 के अतिरिक्त भी एक और प्रक्रिया को अपना लिया गया है, जिसमें निरीक्षक नामक एक पद पर नियुक्ति दी गई है और पेड़ों की कटाई को लेकर 100 रुपए आवेदन शुल्क और 500 रुपए का मुआवजा शुल्क की प्रक्रिया में शामिल कर दिया गया है जो पूर्णतः विधि के विपरीत है।

याचिका में एक पेड़ मां के नाम मुहिम का समर्थन- याचिका में मुहिम चलाई जा रही एक पेड़ मां के नाम के माध्यम से

जगह-जगह पौधे लगाए जा रहे है का समर्थन किया गया है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए और इंदौर में दिन-प्रतिदिन बढ़ते वायु प्रदूषण और समय के साथ बढ़ते गर्म तापमान का सामना करना पड़ रहा है जिसका सीधा असर मानव जीवन, पशु पक्षियों के जीवन पर हमें आए दिन देखने को मिल रहा है। अगर ऐसी स्थिति में भी शहर के पुराने पेड़ों को काटा जाया तो आने वाले लकड़ाने में बढ़ते वायु प्रदूषण, गर्म तापमान, से भविष्य में प्रकृति के वहर का सामना करना बड़ा ही मुश्किल साबित होगा।

पेड़ कटाई की अनुमति को लेकर एक समिति बनाने की मांग- दाय याचिका में एमओजी लाईन और मल्हारांज आश्रम में हुई पेड़ कटाई को लेकर संपूर्ण विवरण दिया गया है। याचिका में पेड़ कटाई को अनुमति को लेकर एक समिति बनाने का भी उच्च न्यायालय से आग्रह किया गया है।

पर्यावरण

डॉ. सौरभ मालवीय

लेखक लखनऊ विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं।

भारत सहित विश्व के अधिकांश देश पर्यावरण संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ग्रीष्मकाल में भयंकर गर्मी पड़ रही है। प्रत्येक वर्ष निरंतर बढ़ता तापमान पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। देश में गर्मी के कारण प्रत्येक वर्ष हजारों लोग दम तोड़ रहे हैं। यह सब ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है। यह पृथ्वी की सहद का दीर्घकालिक ताप है, जो मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न हुआ है। विगत कुछ दशकों में जिस तीव्र गति से जलवायु परिवर्तन हो रहा है वह चर्चा का विषय है। इसके भयंकर दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। कहीं सूखा पड़ रहा है तथा भूजल स्तर बहुत नीचे चला गया है। लोग पेयजल के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली के निवासी भी जल संकट से जूझ रहे हैं। कहीं अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दिल्ली के अनेक क्षेत्र भी बाढ़ की चपेट में आते रहते हैं। देश की राजधानी को इस स्थिति से पता चलता है कि समस्या कितनी गंभीर है। इससे देश के अन्य क्षेत्रों की स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त वायु प्रदूषण भी मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो रहा है। मानव अपने स्वार्थ के लिए निरंतर प्रकृति को हानि पहुंचा रहा है। वनों से वृक्ष काटकर उन्हें समाप्त किया जा रहा है। विकास के नाम पर भी वृक्ष काटे जा रहे हैं। पर्वतों में खनन किया जा रहा है। मानव ने वन समाप्त करके वन्य प्राणियों के लिए आश्रय एवं भोजन का संकट उत्पन्न कर दिया है। कृषि भूमि पर कॉलोनियां बसाई जा रही हैं। इससे कृषि भूमि कम हो रही है। अत्यधिक रसायनों एवं कीटनाशकों के प्रयोग से उपजाऊ भूमि बंजर होती जा रही है। इससे निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्न का संकट उत्पन्न हो सकता है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक जल स्रोत तालाब, जोहड़ व अन्य जलाशय समाप्त हो रहे हैं। नदियां अत्यधिक दूषित एवं विषैली हो रही हैं। इससे जलीय जीवों के लिए संकट उत्पन्न हो गया है। प्लास्टिक कचरे से भी प्रदूषण बढ़ रहा है। इसलिए समस्त जीवों को बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण अत्यंत आवश्यक है।

पर्यावरण शब्द संस्कृत भाषा के ‘परि’ एवं

पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक होने का समय

‘आवरण’ से मिलकर बना है अर्थात जो चारों ओर से घेरे हुए है वही पर्यावरण है। जिस पर्यावरण में हम रहते हैं, हमें उसे संरक्षित करना होगा अर्थात् हमें अपने चारों ओर के वातावरण को संरक्षित करना होगा तथा इसे जीवन के अनुकूल बनाना होगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए जल संरक्षण, मृदा संरक्षण, वन संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण तथा जैव विविधता संरक्षण पर गंभीरता से कार्य करना होगा। यह सर्वविदित है कि मानव शरीर पंचमहाभूत से निर्मित है, जिनमें आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी सम्मिलित है। प्राणियों के लिए वायु एवं जल अत्यंत आवश्यक है। उन्हें जीवित रहने के लिए भोजन भी चाहिए, जो भूमि से प्राप्त होता है। वनों से हमें जीवनदायिनी औषधियां प्राप्त होती हैं। इसलिए हमें वायु, जल, वन एवं मृदा को संरक्षित करना होगा।

जल संरक्षण के लिए प्राकृतिक रूप से बने जलाशयों को संरक्षित करना होगा। नए तालाब बनाने होंगे। जल संग्रहण करना होगा अर्थात् वर्षा के जल को विभिन्न विधियों से संचित करना होगा। तालाब एवं जोहड़ों के अतिरिक्त भूमि के नीचे बनाए गए टैंक के माध्यम से भी वर्षा जल संचयित किया जा सकता है। इसके साथ-साथ जल को व्यर्थ बहने से रोकना होगा। जितनी आवश्यकता हो, उतने ही जल का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त नदियों एवं अन्य जलाशयों को प्रदूषित होने से भी बचाना होगा।

मृदा का संरक्षण भी अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए रिक्त पड़ी भूमि पर पौधारोपण किया जा सकता है। इससे एक ओर हरियाली में वृद्धि होगी, तो दूसरी ओर मृदा कटाव रुकेगा तथा भूमि ऊसर होने से भी बचेगी। इसके अतिरिक्त हानिकारक औद्योगिक कचरे को समाप्त करके भी भूमि को दूषित एवं ऊसर होने से बचाया जा सकता है। प्लास्टिक की थैलियों के स्थान पर कपड़े के थैलों का उपयोग करके प्लास्टिक कचरे को कम किया जा सकता है।

वनों का संरक्षण करके भी पर्यावरण को स्वच्छ बनाया जा सकता है। वन संरक्षण का उद्देश्य यह कि वनों को कटने से बचाया जाए तथा अधिक से अधिक पौधारोपण किया जाए। यदि कहीं विकास कार्यों के कारण वृक्ष काटने अति आवश्यक हों, तो उनसे अधिक संख्या में पौधारोपण किया जाए, जिससे उनकी कमी को

पूर्ण किया जा सके। वन विभिन्न प्राणियों के आश्रय स्थल है। इन्हें सुरक्षित रखकर वन्य जीवों के आश्रय स्थल की भी रक्षा की जा सकती है।

पर्यावरण संरक्षण के लिए देश में कई अधिनियम हैं। इनमें भारतीय वन अधिनियम-1927, वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम-1972, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम- 1974 तथा 1977, वन संरक्षण अधिनियम- 1980, वायु (प्रदूषण एवं नियंत्रण) अधिनियम- 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम-1986, जैव-विविधता



संरक्षण अधिनियम- 2002, राष्ट्रीय जलनीति- 2002, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति- 2004 एवं वन अधिकार अधिनियम- 2006 प्रमुख रूप से सम्मिलित हैं।

सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए कई योजनाएं चला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2021 में घोषित पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अभियान को आगे बढ़ाने के लिए, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दो अग्रणी पहल की हैं। प्रथम ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है, जो पर्यावरणीय गतिविधियों को प्रोत्साहन प्रदान करता है। विगत 13 अक्टूबर, 2023 को अधिसूचित ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम एक अभिन्न बाजार-आधारित व्यवस्था है जिसे व्यक्तियों, समुदायों, निजी क्षेत्र के उद्योगों और कर्पनियों जैसे

विभिन्न हितधारकों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में स्वेच्छिक पर्यावरणीय कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका शासन ढांचा एक अंतर-मंत्रालयी संचालन समिति द्वारा समर्थित है तथा भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के प्रशासक के रूप में कार्य करता है। यह कार्यक्रम कार्यान्वयन, प्रबंधन, निगरानी और संचालन के लिए उत्तरदायी है। यह प्रोग्राम अपने प्रारंभिक चरण में दो प्रमुख गतिविधियों जल संरक्षण और वनीकरण पर ध्यान केंद्रित करता है। ग्रीन क्रेडिट देने के लिए प्रारूप



पद्धति विकसित की गई है और हितधारक परामर्श के लिए इसे अधिसूचित किया जाएगा। ये पद्धतियां प्रत्येक गतिविधि अथवा प्रक्रिया के लिए मानक निर्धारित करती हैं, जिससे सभी क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रभाव और प्रतिस्थापना सुनिश्चित की जा सके। एक उपयोगकर्ता-अनुकूल डिजिटल प्लेटफॉर्म परियोजनाओं के पंजीकरण, उसके सत्यापन और ग्रीन क्रेडिट जारी करने की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करेगा। विशेषज्ञों के साथ भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद द्वारा विकसित किया जा रहा ग्रीन क्रेडिट रजिस्ट्री और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, पंजीकरण और उसके बाद ग्रीन क्रेडिट के क्रय एवं विक्रय की सुविधा प्रदान करेगा।

द्वितीय इंकोमार्क योजना है, जिसका उद्देश्य

पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों को प्रोत्साहन प्रदान करना है। पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली के पीछे का दर्शन व्यक्तिगत विकल्पों और व्यवहार को स्थिरता की ओर ले जाना है। इस दृष्टिकोण के अनुरूप, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपनी इंकोमार्क अधिसूचना को फिर से तैयार किया है, ताकि उपभोक्ता उत्पादों के बीच चयन करने में सक्षम हो सकें और इस तरह उन उत्पादों को चुन सकें जो उनके डिजाइन, प्रक्रिया आदि में पर्यावरण के अनुकूल हैं। जो जलवायु परिवर्तन, स्थिरता और पर्यावरण के प्रति जागरूक प्रथाओं को



प्रोत्साहन देने के लिए देश के सक्रिय दृष्टिकोण का संकेत देती हैं। ये योजनाएं परंपरा एवं संरक्षण में उपस्थित पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को प्रोत्साहित करती हैं, जो पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली की अवधारणा के विचारों को प्रदर्शित करती हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं- ‘हमारे लिए पर्यावरण की रक्षा आस्था का विषय है। हमारे पास प्राकृतिक संसाधन हैं क्योंकि हमारी पिछली पीढ़ियों ने इन संसाधनों की रक्षा की। हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ऐसा ही करना चाहिए।’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी प्रयासों से भारत पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन की दिशा में ठोस पहल करने वाला अग्रणी देश बना है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने पर्यावरण

संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों को दर्शाने वाली एक घटना का उल्लेख करते हुए कहा था कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब गुजरात ‘जलवायु परिवर्तन विभाग’ वाला देश का प्रथम राज्य बना था। यह एक अनूठा प्रयास था, जबकि तब केंद्रीय स्तर पर पर्यावरण मंत्रालय ने भी जलवायु परिवर्तन की अवधारणा को एकीकृत नहीं किया था।

लोकसभा चुनाव के भारतीय जनता पार्टी के ‘भाजपा का संकल्प मोदी की गारंटी 2024’ नामक घोषणा पत्र में पर्यावरण का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई पर्यावरण के लिए जीवन शैली की अवधारणा को विश्व ने स्वीकार किया है। इस मंत्र को साकार करने के लिए हमने पर्यावरण प्रबंधन के सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया है। हम पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली में विश्व का नेतृत्व करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम पारंपरिक ज्ञान के साथ-साथ आधुनिक प्रथाओं का उपयोग करके एक स्वस्थ समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध हों। हमने कई ऐसी योजनाएं क्रियान्वित की हैं, जिससे पर्यावरण की सुरक्षा होगी। जैसे प्रधानमंत्री सूर्य का घर योजना, रेलवे का विद्युतीकरण, ई-बस, इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रसार एथेनॉल और बांयो फ्यूल का उपयोग इत्यादि। इन सब योजनाओं से हम नेट जीरो के लक्ष्य की प्राप्ति की ओर तीव्र गति से अग्रसर हैं तथा इन योजनाओं से हमारे नागरिकों के लिए वातावरण सुनिश्चित होगा।

विगत विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पौधा लगाकर ‘एक पौधा मां के नाम’ नामक अभियान प्रारंभ किया। उन्होंने एक्स पर लिखा था- ‘मैंने प्रकृति मां की रक्षा करने और सतत जीवन शैली अपनाने की हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप एक पेड़ लगाया। मैं आप सभी से यह आग्रह करता हूं कि आप भी हमारे ग्रह को बेहतर बनाने में योगदान दें।’

इसमें दो मत नहीं है कि सरकारी प्रयास एवं जनभागीदारी से पर्यावरण को संरक्षण किया जा सकता है। हमें अपने बच्चों को भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वातावरण मिल सके।

स्वच्छ भारत के नक्शे में क्यों नजर नहीं आती स्लम बस्तियां?

मुद्दा

ईशा कुमारी

देश को स्वच्छ बनाने के लिए पिछले कुछ वर्षों से केंद्र के स्तर पर लगातार प्रयास किये जाते रहे हैं. एक ओर जहां स्वच्छ भारत अभियान चलाया जाता है वहीं दूसरी ओर राज्य के साथ साथ शहरी स्तर पर भी स्वच्छता सर्वेक्षण कराये जा रहे हैं. जिसमें देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया जाता है. इसमें देश के सबसे साफ शहर को महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भी किया जाता है. स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की अखिल भारतीय रैंकिंग में बिहार को 27 राज्यों में 15वां स्थान मिला है. वहीं इस सर्वेक्षण में बिहार के 142 शहर शामिल हुए थे. इस बार के सर्वेक्षण में राजधानी पटना ने अपनी स्थिति को सुधारा अवश्य है लेकिन अब भी वह टॉप 10 की सूची से बहुत दूर है. एक लाख से ज्यादा की आबादी वाले शहरों में पटना की औलंडईया रैंकिंग 77 रही. यह सर्वेक्षण बताता है कि एक राजधानी के तौर पर पटना को स्वच्छता की दिशा में अभी और कई महत्वपूर्ण कदम उठाने बाकी है.

दरअसल पटना के कुछ इलाके अभी भी ऐसे हैं जहां आज भी साफ़-सफाई बहुत अधिक नजर नहीं आती है. इन्हीं में एक अदालतगंज स्थित स्लम बस्ती भी है. जहां स्वच्छता का विशेष प्रभाव नजर नहीं आता है. पटना सचिवालय से कुछ ही दूरी पर स्थित इस स्लम बस्ती की आबादी लगभग एक हजार के आसपास है. जहां करीब 60 प्रतिशत ओबीसी और 20 प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदाय निवास करते हैं. तीन मोहल्ले अदालतगंज, ईंख कॉलोनी और झाड़वर कॉलोनी में विभाजित इस स्लम परिया में साफ़ सफाई की बहुत कमी नजर आती है. हालांकि स्वच्छ भारत के तहत कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां भी यहां आती हैं. जिससे यहां के लोगों का कहना है कि यह गाड़ियां नियमित रूप से नहीं आती हैं, जिसके कारण गंदगी और कूड़े का ढेर जमा हो जाता है. जिससे आसपास की हवा प्रदूषित होती है और इसका प्रभाव यहां रहने वाले बच्चों की सेहत पर देखने को मिलता है. इस संबंध में बस्ती की 18 वर्षीय नंदिनी कहती है कि ‘हमारे बस्ती की स्थिति बहुत दयनीय है. जहां तहां कूड़ा फैला रहता है. जो सड़क और नाली में बहता है. जिससे निकलने वाली दुर्गंध से लोग परेशान रहते हैं. वहीं 70 वर्षीय रामकली देवी कहती हैं कि ‘कूड़े कचरे से निकलने वाली दुर्गंध से सांस लेना मुश्किल हो जाता है. प्रतिदिन कचरा गाड़ी के नहीं आने के कारण अक्सर लोग अपने घर का कूड़ा बाहर फेंक देते हैं. जिससे कॉलोनी की हवा प्रदूषित होती रहती है.’ यह कहती हैं कि ‘यदि इन कूड़े को कॉलोनी से बाहर फेंकने के लिए कोई एक स्थान नियमित कर दिया जाए तो समस्या का हल निकल सकता है. लेकिन नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा ऐसा नहीं करने दिया जाता है. वहीं कूड़े वाली गाड़ी जब नियमित रूप से नहीं आणी तो लोग अपने घर का कूड़ा इधर उधर ही फेंकेंगे.’ वहीं 32 वर्षीय पिकी देवी कहती हैं कि ‘जब कचरा उठाने वाली गाड़ी कॉलोनी में नहीं आती है तो हम अपने घर का कचरा बाहर रख देते हैं. जिसे आबारा कुत्ते खाने की लालच में फाड़ कर इधर उधर बिखरा देते हैं. अक्सर वह कचरे या तो कॉलोनी की रोड पर पड़े होते हैं या उड़ कर नालियों में चले जाते हैं.’ पिकी देवी कहती हैं कि अक्सर कॉलोनी के बच्चे गिप्स और कुड़कुड़े खाकर उसके पैकेट नालियों में फेंक देते हैं. जिससे वह जाम हो जाता है और उसका गंदा पानी सड़क और आसपास के घर तक पहुंच जाता है. जिससे न केवल लोगों को परेशानी होती है बल्कि इससे बीमारियों के फैलने का भी खतरा बना रहता

है. अब बारिश का मौसम आ गया है. ऐसे में इन कचड़ों की वजह से जाम होती नालियां और भी अधिक उफनने लगेंगी. इसका पानी आसपास के घरों के अंदर तक चला जाता है. यदि कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां प्रतिदिन आएंगी तो इस प्रकार की समस्या का काफी हद तक हल संभव है.’

वहीं 12वीं में पढ़ने वाली 17 वर्षीय निकिता कहती है कि ‘अक्सर कॉलोनी की लड़कियां माहवारी के दौरान इस्तेमाल किये पैडस को सही जगह डंप करने की बजाए इधर उधर फेंक देती हैं. जिन पर मखियां बैठती हैं और वही मखियां फिर लोगों के खाने पर बैठ कर उन्हें दूषित कर बीमार कर देती हैं. अधिकतर किशोरियां इससे फैलने वाली बिमारियों से अनजान होती हैं.’ वह कहती है कि इसके बारे में कई बार स्कूल में भी बताया जाता है और लड़कियां इसका ख्याल भी रखती हैं, लेकिन घर पर इसके उचित निस्तारण की व्यवस्था नहीं होने के कारण वह इसे खुले में फेंकने पर मजबूर हो जाती हैं. कॉलोनी की बुजुर्ग सुष्मा देवी कहती हैं कि पटना में कई स्थानों पर विकास कार्य चल रहे हैं. इसके तहत पुल और ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है. अदालतगंज के करीब भी आवागमन को सुलभ बनाने के लिए एक पुल का निर्माण किया जा रहा है. इसके लिए इस स्लम बस्ती के पास से गुजरने वाले बड़े नाले को ब्लॉक कर दिया गया है. जिससे उसका सारा गंदा पानी अदालतगंज और झाड़वर कॉलोनी में फैल रहा है. इससे जहां लोगों को आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वहीं दूसरी ओर यह बिमारियों का भी कारण बनता जा रहा है. अब जबकि मानसून ने बिहार में दस्तक दे दी है तो बारिश में इसका पानी और भी तेजी से फैलने का खतरा बन जाएगा.

इस स्लम बस्ती में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र की सैविका लक्ष्मी देवी और सहायिका मेजर देवी बताती हैं कि इस बस्ती में कोई भी आशा कर्कर की नियुक्ति नहीं है. ऐसे में यदि कोई गंभवर्ती महिला या बच्चे बीमार होते हैं तो वही उन्हें अस्पताल में एडमिट कराने का काम करती हैं. अधिकतर बच्चे गंदगी से फैलने वाली बीमारी के शिकार होते हैं. यदि इस स्लम बस्ती में साफ सफाई का समुचित ध्यान रखा जाए तो बहुत से बच्चों को बीमारी से बचाया जा सकता है. वह कहती हैं कि अक्सर लोग जागरूकता के अभाव में स्वच्छता के महत्व से अनजान रहते हैं. जिसकी वजह से वह घर के कूड़े को इधर उधर फेंक देते हैं. वहीं समाज सेविका फलक कहती है कि ‘इस स्लम परिया के लोगों का कहना सही है कि कई बार दो तीन दिनों तक कूड़ा उठाने वाली गाड़ी यहां आती ही नहीं है. लेकिन यदि लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हो जाए तो इसका समाधान निकाला जा सकता है. इसके लिए बस्ती वालों को सामाजिक स्तर पर योजनाबद्ध रूप से काम करने की जरूरत है. सूखे और गीले कचरे को अलग कर उसके डंप करने की व्यवस्था करने की जरूरत है.’ वह कहती हैं कि हर बात के लिए सरकार और प्रशासन को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है. यदि कॉलोनी के लोग सामाजिक रूप से इसका हल तलाशें तो प्रतिदिन कचरे का स्थाई निस्तारण संभव हो सकता है.

स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में जिन मापदंडों के आधार पर स्वच्छ शहर का चयन किया गया था उसमें कूड़ा इकठ्ठा करना, ट्रांसपोर्ट करना, कूड़े को प्रोसेस और नष्ट करना, सस्टेनेबल सैंटिशन, इलाके का सौंदर्यीकरण, अतिक्रमण और नाली के पानी का ट्रीटमेंट प्रमुख रूप से शामिल था. इस आधार पर यदि हम अदालतगंज के इस स्लम बस्ती का जायजा लें तो इसमें काफी कमियां नजर आएंगी. हालांकि इस कमी को दूर किया जा सकता है. लेकिन केवल प्रशासन और नगर निगम के ऊपर जिम्मेदारी डाल कर हम इससे मुक्त नहीं हो सकते हैं बल्कि इसके लिए सामाजिक स्तर पर जागरूकता फैलाने की जरूरत है. यह बताने की जरूरत है कि यदि कचड़ा उठाने वाली गाड़ी किसी कारणवश नहीं आती है तो इसका अस्थाई प्रबंधन किस प्रकार किया जाए कि वह इधर उधर न फैले. शायद इस प्रकार के छोटे छोटे कदम ही अदालतगंज जैसे स्लम बस्तियों को स्वच्छ भारत के नक्शे पर प्रमुखता से उभार सकते हैं. (चरखा फीचर)

दृष्टिकोण

बादल सरोज

लेखक लोकजतन के संपादक हैं।

कुछहजार करोड़में बने और अभी अभी प्राणप्रतिष्ठित बताये जाने वाले अयोध्या के मन्दिर की रिसन और उसकी ओर जाने वाली सड़कों का पाताल में समाना रुका भी नहीं था कि पुल गिरने लगे। ऐसे गिरे कि गिरते ही जा रहे हैं और खरबूजे को देखकर खरबूजे रंग बदलते हैं की तर्ज पर गिरते पुल को देख पुल गिरते हैं की नई कहवात गढ़ रहे हैं। रफ्तार कुछऐसी है कि एक के गिरने की धमक रुकती नहीं कि दूसरा टूटकर टपक जाता है। बिहार में अकेले एक दिन में 5 पुल गिरे, 19 दिन में 13 गिरे - इन पिकियों के लिखते लिखते उनकी संख्या 15 हो गयी है। इनकी देखा देखी पड़ोसी राज्य झारखण्ड की अरणा नदी का पुल गिर गया तो दूरस्थ प्रदेश उत्तराखण्ड में एक पुल पूरे का पूरा ही बह गया। मध्यप्रदेश में पिछली बारिश में ही इतने सारे गिर चुके थे बाद में गिरने के लिए लागभग कोई बचा ही नहीं।

इतिहास में इस कालखण्ड को पुलों के टूटने, दरकने, गिरने और बहने के कालखण्ड के नाम से जाना जाएगा। ये पुल अपने आप नहीं गिर रहे हैं - अनायास नहीं गिर रहे हैं ; इन्हें गिराने के समुचित प्रबंध किये गए थे, खूब जतन के साथ इन पर अमल किया गया था। ईंट-गारे, बजरी, सीमेंट के गिरे हुए पुल थोड़ा शोर, थोड़े स्वापे, एक दूसरे के सर पर हांडी फोड़ने और मिलमिलाकर एक दूसरे को साफ़ बचाने के कर्मकाण्ड के बाद फिर से गिरने के लिए एक बार फिर बना दिए जायेंगे। मगर असली चिंता उन पुलों की है और जिन्हें कारपोरेट की गोद में बैठे हिन्दुत्व के कुनबे ने हमशा के लिए गिरा देने का बीड़ा उठया हुआ है। मौजूदा निजाम ने सत्ता में पहुँचने के बाद पुलों ड़ुहर तरह के पुलों - को तोड़ने और कमजोर करने का काम ही तो किया है। हजार, दो हजार, पाँच हजार साल में बने पुलों को हिलाने, उनकी नींवों को झकझोरने, उनमें पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।

सभ्यताओं के निर्माण की असल कहानी अनगिनत पुलों के बनने और बनाए जाने की कहानी है। जंगल से निकलने के बाद अलग अलग कबीलों, कुटुम्बों, नस्लों, प्रजातियों और संस्कृतियों ने एक दूजे तक पहुँच बनाने के लिए धीरज के साथ ऐसे पुल बनाए जिनसे आना और जाना दोनों सहज बनाया जा सके। संस्कृतियाँ इसी मेल जोड़ से बनी संवरी, सभ्यताओं ने इन्ही पुलों के मजबूत ढाँचों की बुनियाद पर खड़े होकर अपनी ऊँचाईयाँ हासिल कीं और तलहटि पहुँचीं। कच्चे अधबने मकानों को घर में और घरों के योग को समाज के रूप में ढाला भी- संजोया भी। ऐसे वैसे कई युग गुजरने के बाद यही समाज राज्यों और देशों के रूप में संगठित और पुनर्गठित हुए। खुद भारत इसकी जीती जागती और अनूठी मिसाल है। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी प्रसिद्द कविता ‘भारत तीर्थ’ में विस्तार से इसे दर्ज किया। उसकी शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि;

‘हे मरो चित्त पुण्य तीर्थ जागो रे धीरे /एँ भारते महामानवर सागर तीरे / हेथाय दांडाप डु बाहू बाडये / नमि नर देवतारे / हेथा आर्य हेथा अनार्य शक-हुन दल पाठन-मोगल एक देहे होलो लीन / एँ भारते महामानवर सागर तीरे / दांडरे धीरे !!’

(कोई नहीं जानता किसके आह्वान पर मनुष्य की

गिर रहे हैं और भी पुल और बहुत सारे

कितनी धारायें प्रबल वेग से आई, किधर से आई और मिल कर भारत के मानवों के महासागर में हो गयी विलीन। यहाँ आर्य हैं अनार्य, हैं द्रविड़ और चीनी, शक, हूण के जत्थे, मुगल और पठान सब एक देह में लीन। पश्चिम के द्वार खुले हैं आज, सब वहाँ से ला रहे हैं उपहार/ इस भारत के महामानव के समुद्र तट पर वे/ दोंगे और लेंगे, मिलायेंगे और मिलेंगे। जायेंगे नहीं लौट कर।)

इसे ही फ़िराक गोरखपुरी साहब ने अपनी तरह से कहा कि;

‘सरजमीने हिन्द पर अक्राम-ए-आलम के फ़िराक काफ़िले बसते गए, हिन्दोस्तां बनता गया।’ (अक्रामे आलम = दुनिया भर की कौमों) यहाँ सिर्फ़ दो का कहा लिखा गया है। किन्तु यही बात भारत में मौजूद 8 भाषा परिवारों की 1652 मातृभाषाओं और 19500 बोलियों में किसी न किसी तरह से दर्ज की



गयी। उस संस्कृत और फारसी में भी जिसे आर्य और बाकी आगंतुक अपने साथ लाये थे, उन द्रविड़ भाषाओं में भी जिन्हें इन सबके आने के सैकड़ों वर्ष पहले से यहाँ रहने वालों ने संजोकर रखा था।

बहरहाल ऐसा, रातोंरात अपने आप नहीं हो गया था। गुरुदेव जिन्हें मनुष्य की कितनी धारायें और फ़िराक जिन्हें दुनिया भर की कौमों बताते हैं वे शक, हूण, कुषाण, यवन, तुर्क, मंगोल, पठान, गुर्जर, आर्य, पारसी, यहूदी और क्रिस्तान और उससे हजारों साल पूर्व पाँव पाँव यूरोप और एशिया की तय करते अफ़्रीकन, हिन्दुकुश के पर्वतों, हिमालय की श्रृंखलाओं और घाटियों को लांघते, असीम कष्ट सहते इस भूखण्ड पर आये और फिर यहीं के होकर रह गए। रहते बसते आपस में जुड़ने के लिए पुल बनाये, दिया भी लिया भी, मिले भी मिलया भी और इस तरह के अनगिनत पुलों से बना वह हिन्दुस्तान जिसे अब भारत देट इज इंडिया के नाम से जाना जाता है और जिसकी तासीर ‘कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी / सदियों रह है दुश्मन दौर जर्मा हमारा’ के सूत्र में अल्लामा इकबाल ने बयान की है।

कुल जमा यह कि भारत घाटों का जोड़ है ड़ुधर की उधर की ईंटों के मेलमिलाप का जोड़ है - इन्ही पुलों के मेल और जोड़ से खिली है अनेकता में एकता की शानदार मिसाल विविध संस्कृतियों वाली रंगबिरंगे फूलों की बगिया। इस देश का दुर्भाग्य है कि उसकी बागडोर उनके हाथों में हैं जो इन पुलों को तोड़ने और बगिया को उजाड़ने में लगे हैं।

लिहाजा वास्तविक फ़िर्क की बात ये पुल हैं। पहली बारिश में कागज़ की तरह बह गए पुल तो बन बना जायेंगे - लेकिन हजारों साल की बारिश आंधी और बाढ़ में अंडिा बने रहे ये पुराने पुल अगर दरक गए तो लम्हों की खता की सजा सदियों को भुगतनी पड़ सकती है। इस कुनबे का निशाना अनेकता में एकता की नींव पर है, सदियों पुराने संग साथ पर है। उनके निशाने पर भाषाएँ हैं; वे एक देश एक भाषा के नाम

पर बाकी सबको पहले दोयम दर्जे पर और आखिर में विलुप्ति की कागार पर पहुंचाना चाते हैं। नीट जैसी केंद्रीकृत प्रतियोगी परीक्षाओं और अपराध की नई संहिताओं के नामकरण के जरिये ये इसकी शुरुआत कर भी चुके हैं। दूसरी भाषाएँ तो हैं ही उनके निशाने पर खुद उनकी भाषा है जिसे असंस्कारित. अभद्र और अशिष्ट बनाकर दुर्भाषा बन भी रहे है, बना भी रहे हैं।

विधवाओं और शूद्रों को जीवित ही फूंक देने वाले बर्बर युग से थोड़े बहुत सभ्य समाज तक लाने के लिए राजा राममोहन रायों, ईश्वरचंद्र विद्यासागरों, विवेकानन्दों से होते हुए जातिबा और साक्षित्री फूले, पेरियारों और अम्बेडकरों से लेकर सुधार आन्दोलनो और वामपंथ की तहरीकों ने पुल बनाये थे; कुर्गीत्यों और अंधविश्वास की थंभर पर करने के लिए बनाये गए इन पुलों को ढ़ाकर सामाजिक भूगोल को एक बार फिर मनु और गीताओं के ऊबड़ खाबड़ में तब्दील करने की मुहिम छेड़ दी गयी है। बुद्ध, नानक द्वारा तामीर किये गए पुल तोड़ने की धुन में समाज को आईना दिखाने वाले साहित्य और उसके भी प्रयत्नों से बनी संवरी साझी संस्कृति के मजबूत पुलों की जड़ों में मद्गु ढ़ाला जा रहा है।

सबसे योजनाबद्ध हथौड़ा उस शिक्षा पर चलाया जा रहा है जिसने कंदराओं के युग को वापस कन्दरा में धकेल कर, मस्तिष्कों में जमे अधैरों को झ़ाका रोशनी में बदला था। आर्यभट्टों, वराह मिहिर से भाषा और विक्रम

साराभाई जैसों के अंतरिक्ष विज्ञान की जगह फ़लित ज्योतिष और हाथ की रेखाओं में लिखी नयिती को बिठया जा रहा है। विश्वविद्यालय मनुष्य को इसान बनाने की कठिन राह के भरोसेमंद पुल थे ड़ु उनमें भेड़ियों की माँदे बनाई जा रही है। मनुष्य और पशु में एकमात्र अंतर, प्रकृति आश्रित असहाय पशु जीवन से समर्थ और प्रकृति को भी नियंत्रित करने की क्षमता वाला मनुष्य बनने की एकमात्र वजह श्रम थी; श्रम ही वह पुल था जिसकी मदद से मनुष्य और समाज अस्तित्व में आया था। श्रम से हासिल मूक्य ही वह ईशान था जिससे उसकी गाड़ी सरपट दौड़ सकती है। मौजूदा निजाम श्रम के पहले से ही सीमित अवसरों को भी छीन कर उसे कातर याचक में बदल रहा है। सबसे बड़कर सविधान और कानून के राज के उस पुल को ईंट ईंट करके तोड़ा जा रहा है जिसने भारत को भारत बनाया। पुलों के तोड़ने उन्हें झ़कझोरने नहीं होगा; सार की बात यह है कि मनुष्य और उसका समाज कोई स्थिरांक नहीं है - हमेशा गतिशील है। यह गति यदि आगे की ओर नहीं होगी तो पीछे की रपटली ढ़लान की तरफ होगी। मनुष्य के ईसान बनाने की सम्भावनाओं के जितने भी पुल हैं यदि वे तोड़ दिए जायेंगे तो उसका हैवान बनना तय है। उसे बर्बर बनाने की मुहिम भी जारी है।

युद्ध शास्त्र बताता है कि पराजित होकर पीछे की ओर भागने वाली सेनाये जिन पुलों से गुजरती हैं उन्हें ध्वस्त करती जाती हैं। मौजूदा हुक्मरान भी कुछइसी तरहका आचरण कर रहे हैं। ठीक यही वजह है कि नदी नालों पर बने पुलों के गिरने के दोषियों की शिनाख़्त करते हुए, उन्हें सजा दिलाने की मांग उठाते हुए, समाज को जोड़ने वाले पुलों को तोड़ने वालों की पहचान करना और उन्हें उनके इस अपराध के लिए दण्डित करने के लिए भी उठना होगा। अच्छे बात है कि जिन दिनों में ये हमले तेज हुए हैं उन्ही दिनों में इनके खिलाफ़ प्रतिरोध भी बढ़ा है।



केन्द्रीय मंत्री और विधायक का तुलादान आज

बैतूल। मां मानवा जन्मोत्सव समिति द्वारा आज 20 जुलाई (शनिवार को) सुबह 11 बजे क्रीड़ा परिसर अर्जुन वार्ड, दुर्गा वार्ड में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गा दास उदके और विधायक हेमंत खंडेलवाल का तुलनादान किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गा दास उदके और विधायक बैतूल हेमंत खंडेलवाल शिरकत करेंगे। उनके साथ विशेष अतिथि के रूप में भाजपा जिलाध्यक्ष आदित्य बबला शुक्ला, नरन पालिका अध्यक्ष पार्वती बाई बारस्कर, और नरन पालिका उपाध्यक्ष महेश राठौर की उपस्थिति भी होगी। कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण तुलनादान का आयोजन होगा, जो मां मानवा जन्मोत्सव समिति द्वारा किया जाएगा। इसके बाद भोजन प्रसादी का आयोजन भी होगा। इस मौके पर एक पैथरोपेन कार्यक्रम भी रखा गया है, जिसमें एक पेड़ का में नाम का लगाया जाएगा। यह पहल पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की जा रही है। समिति के संयोजक आनंद प्रजापति ने इस आयोजन की जानकारी दी और समस्त देवतुल्य कार्यक्रमों पर अपील एवं आमजन से उपस्थिति की अपील की है।

मलेरिया प्रभावित ब्लॉक में 'मलेरिया ऑफ-200' का शुभारंभ

बैतूल। आयुक्त संचालनालय आयुष म.प्र. के दिशानुसार और डॉ. योगेश प्रभाविक, प्र.जिला आयुष अधिकारी बैतूल के मार्गदर्शन में 'मलेरिया चक्रवर्ति ब्लाक शाहपुर औषध पट्टन' में 'मलेरिया रोग नियंत्रण' अभियान 2024 का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर आयुष विभाग के घर-घर जाकर मलेरिया ऑफ-200 की पहली खुराक खिलाई। मलेरिया ऑफ-200 को नोडल ऑफिसर श्री राजपूत ने बताया कि शाहपुर में नगर परिषद उपाध्यक्ष पम्मी राठौर और प्रभात पटना में ग्राम अमोरी की उपसरपंच सुशीला राजकुमार साने ने इस अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान हेमोथीयो रोग प्रतिरोधक औषध 'मलेरिया ऑफ-200' की पहली खुराक खिलाई गई। 18 जुलाई 2024 से 3 सप्ताह तक और फिर 22 अगस्त से पुनः 3 सप्ताह तक यह दवा वितरित की जाएगी।

जिला स्तरीय रोजगार मेले में 336 अभ्यर्थियों का हुआ चयन

बैतूल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की प्रेरणा से युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने प्रदर्शक की नई सोच और चेतना को मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से कोलेक्टर नेरुद कुमारा सूर्यवंशी की निदेशानुसार शासकीय एकलव्य महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बैतूल में गुरुवार को जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भोपाल कोशल विकास एवं रोजगार विभाग के उप संचालक मनोज कुमार अग्निहोत्री, सहायक संचालक डॉ.बी.ए. खान, संस्था आईएमसी के अध्यक्ष पीयूष तिवारी, आईएमसी सदस्य श्री विवेक शुक्ला उपस्थित थे। संस्था प्राचार्य रंजनाकर पंडाजी ने बताया कि मेले में 845 अर्थर्थियों ने अपना पंजीजन कराया था। रोजगार मेले में उपस्थित कंपनियों ने ऑन स्पॉट साक्षात्कार के माध्यम से 336 अर्थर्थियों का चयन किया गया। उन्होंने बताया कि वर्धमान फेब्रिक्स लिमिटेड बुदनी में 82, टाटा मोटर्स सऊद अहमदाबाद में 18, बजाज ऑटो लिमिटेड औरंगाबाद और पुणे में 11, श्राइड एसई इलेक्ट्रिकल्स हैदराबाद में 5, विस्टान इफॉर्का में बैंगलोर 7, टाटा मोटर्स पुणे में 50, फॉक्सकॉन लिमिटेड बैंगलोर में 135 अर्थर्थियों को चर्चानत किया है। इसके अलावा क्लोस्टर ब्रदर्स लिमिटेड देवास द्वारा कुल 28 अर्थर्थियों को ऑफर लेटर प्रदान किया गया। मेला प्रभावशीलता दिवसीय कुमार सोनी ने बताया कि वर्धमान फेब्रिक्स लिमिटेड बुदनी के चर्चानतों को 24 जुलाई 2024 को ज्वाइन कराने हेतु कंपनी के खर्च पर बुदनी भेजा जाएगा। एलएसएमई ऑफिसर विवेक दायमा ने उपस्थित सभी कंपनियों के प्रतिनिधियों वर्धमान फेब्रिक्स लिमिटेड बुदनी अजय मालवीय, क्रीस कॉर्प नरैज ठाकुर एवं कु. वंदना राजपाल एवं समस्त स्टॉफ का आभार व्यक्त किया।

बदइंतजामी से पड़ा ब्लड बैंक में रक्त का टोटा



बैतूल। रक्तदान को लेकर मध्यप्रदेश में कभी टॉप लिस्ट में शुमार जिला चिकित्सायात्रा को ब्वाड मुख्य इन दिनों रक्त की कमी से बुरी तरह से जूझ रहा है। इसके पीछे मुख्य कारण यह सामने आया है कि यहां पर बर्द्धजागी की वजह से लगातार हो रही रक्तदाताओं की उपेक्षा से उनमें आक्रोश व्याप्त होने लगा है और उनका रक्तदान करने के प्रति मोहभंग हो रहा है। ब्वाड बैक में रक्त की कमी से सबसे अधिक खामियाजा सिकलसेल और थैलेसिमिया पीडिड लगभग 400 बच्चों को उठाना पड़ रहा है। हर तीन माह में रक्तदान करने वाले सदीप सोलंकी ने बताया कि सबसे अधिक रक्त की आवश्यकता सिकलसेल पीडिड बच्चों को 1 माह में और थैलेसिमिया पीडिड बच्चों 15 दिन में रक्त की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को होती है। उनकी जान पर बन आने के कारण ही जिले के रक्तदाताओं द्वारा ग्री, ठाउ और बारिश को देखे बिना सीधे जान बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं और अपना बहुमूल्य रक्त दान करते हैं। लेकिन चार माह से ब्वाड बैक में लगातार रक्तदाताओं की उपेक्षा होने से यहां पर ब्वाड का टोटा पड़ गया है। इस बारे में डॉ. डब्ल्यू.ए. नागले, रक्त कोष अधिकारी, बैतूल ने बताया कि बैक में रक्त की कमी है। अभी दो शिविर रविवार और मंगलवार को लगने वाले हैं। समस्या का कारण डोनर नहीं मिलना है। मेटर्निटी, सिकलसेल और थैलेसिमिया के लिए प्लाना एकस सेल के रक्त देवें हैं। व्यवस्था सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं।

पत्रकारिता जनसंचार में करियर की अपार संभावनाएं : दीक्षित

आरडी पब्लिक स्कूल बैतूल में आयोजित हुई कार्यशाला

बैतूल। उक्त शिक्षा संस्थान के रूप में स्थापित हो चुके आरडी पब्लिक स्कूल बैतूल में विद्यार्थियों को क्रांतिदि एजुकेशन देने के साथ ही उनके उज्ज्वल भविष्य निर्माण के लिए रोजगारोन्मुखी क्षेत्रों पर केन्द्रित वर्कशॉप आयोजित कर करियर गाइडेंस भी दिया जा रहा है। आरडी पब्लिक स्कूल की डायरेक्टर श्रुति खण्डेलवाल के मार्गदर्शन में 19 जुलाई को 'पत्रकारिता एवं जनसंचार' विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में आरडी पब्लिक स्कूल बैतूल के पूर्व छात्र एवं वर्तमान में एमिटी विश्वविद्यालय में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहे आदेश दीक्षित ने कक्षा 11वीं एवं 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता एवं जनसंचार में करियर की अपनार संधावनायें हैं।

पुर्नवास एरिया में पट्टेधारियों के साथ सरकारी जमीन पर दबंगाइयों का कब्जा



बैतूल। बैतूल के पुनर्वास क्षेत्र में कुछ लोग अपने समाज के साथियों के नाम जारी पट्टे की जमीन पर दबंगाई करते हुए कब्जा जमा लिया है



शुरू कर दिया है। इस आशय को लेकर पीड़ित परिवार ने 19 जुलाई शुक्रवार को कलेक्टर, एसपी, एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है।

बैतूल के सोनाघाटी पुनर्वास केंद्र के पीड़ित परिवारों का नेतृत्व कर रही संगीता सोलंकी द्वारा 19 जुलाई को सौंपे ज्ञापन में कलेक्टर एसपी को इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप कर कार्रवाई करने का आग्रह किया है। उन्होंने ज्ञापन पत्र के माध्यम से मांग

को है कि जिला प्रशासन द्वारा पुनर्वसि योजना के तहत आवंटित पट्टे की भूमि पर जिन लोगों के नाम पट्टे आवंटित की गई है उन्हें ही उनके पट्टे की भूमि पर बसने दिया जाए। परंतु पिछले कुछ दिनों से अपराधिक प्रवृत्ति के लोग जिसमें पवन, कमल, गोपाल, शाहरुख शाहमिल है जो कि गंभीर मामलों के आरोपी भी हैं उनके द्वारा अन्य प्राधिकारित पट्टे की भूमि पर कब्जा जमा कर मकान दुकान बनाना शुरू कर दिए हैं। और तो और जिन लोगों के ग्राम

चौथिया में पक्का मकान है, उन्हें भी यहां बुलाकर बसाने का काम किया जा रहा है जिसके नाम से यहां पर कोई पट्टे की भूमि नहीं है। इस तरह इन



ज्ञापन पत्र के माध्यम से कलेक्टर-एम्पली
ऑर एसडीओ को आग्रह किया है कि वे इस संदर्भ में
मैंने जिक्र नाम पट्टे आवंटित है उन्हें भी विस्थापित
करने में एक्शन लेकर मदद करें तथा
आवंटित प्लॉट नंबर एक के सामने सरकारी
भूमि में अवैध निर्माण को हटाने का कार्रवाई
करें। शासकीय भूमि पर अवैध तरीके से बना
रह दुकान से प्लॉट 1/13 को परेशानी खड़ी
होगी, वही उनके चक्र में और भी अतिक्रमण
की संभावनाएं बढ़ जाणी, जिससे स्थिति बिगड़
और भी विकट हो सकती है। सामने यह
विस्थापित परिवार को मुश्किल को सहन
करना पड़ सकता है। इसलिए आपसे आग्रह
है कि यहां अन्य विस्थापितों को सुकून के
साथ अपना जीवन बसर करने आवश्यक
कार्रवाई करें।

इनका कहना

गैर कानूनी तरीके से कोई किसी अन्य पट्टाधारी के जमीन पर अतिक्रमण नहीं कर सकता। और ना ही कोई शासकीय भूमि पर बेजा कब्जा कर सकता। इस संदर्भ में जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

- नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी,
कलेक्टर, बैतूल

नियमों के उल्लंघन पर यातायात पुलिस द्वारा की जा रही कार्यवाही



बैतूल। बस संचालकों द्वारा जगह-जगह बस खड़ी करके सवारी लेने पर जहां ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है वहां दुर्घटना का भय भी बना रहता है। गैरतलब है कि शहर में सुचारु रूप से ट्रैफिक के संचालन के लिए पिछले दिनों विधायक हेमंत खड्गे ने अथकता में यातायात समिति की बैठक हुई थी, जिसमें विधायक ने अधिकारियों को दो दृढ़ निर्देश दिए थे कि शहर में बसों की निर्धारित स्थान पर ही खड़ी की जाए, जगह-जगह बस खड़ी करके सवारी लेने वाले बस संचालकों पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश उन्हें अधिकारियों को दिए थे। इसी त्रासदी में आज एक बस संचालक पर यातायात पुलिस ने दो हजार का जुर्माना किया। यातायात पुलिस थाना प्रभारी गजेंद्र कैन ने बताया कि बस स्टैंड तथा अन्य बस स्टॉपज के बाहर रोड पर बस खड़ी करके सवारी चढ़ाने-उतारने पर यातायात पुलिस द्वारा लगातार हदियात देने के बावजूद भी कुछ बस संचालकों द्वारा हदियात की अवहेलना की जा रही है। जिस पर बैतूल यातायात पुलिस द्वारा वेदशं ड्रेवल की बस पर आदेशों की अवहेलना के उद्घेन करने पर बस मालिक पर 2000 रूपरुप का जुर्माना किया गया है। यदि दोबारा उद्घेन किया जाता है तो परमिट की शर्तों के उद्घेन पर 10000 रूपरुप का जुर्माना एवं श्रेयो प्रविहन अधिकारी के माध्यम से परमिट निरस्तकरण की कार्यवाही की जाएगी।

कुटी में 13 किंटल टिक्कड़ और सवा किंटल की बनेगी चटनी



हलवा, पुड़ी और सब्जी का वितरण किया जाएगा। यहां की टिकड़ चटनी की प्रसादी श्रद्धालुओं को खूब पसंद आती है। प्रतिवर्ष दशरथ की कुटी समिति द्वारा प्रसादी के रूप में टिकड़, चटनी बनाई जाती है। मंदिर समिति के अध्यक्ष प्रवीण पम्पू भावसार ने बताया कि इस वर्ष गुरुप्रणिधि के अवसर पर दादाजी की कुटी में 13 किंटल का टिकड़, सवा किंटल की चटनी, 6 किंटल की पुड़ी, 10 किंटल की सब्जी और 2 किंटल का हलवा बनाया जाएगा। प्रसादी के रूप में श्रद्धालुओं को टिकड़ चटनी वितरित करेंगे। लगभग 50 हजार श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है।

पर दादाजी की कुटी में 13 किंटल का टिकड़, सवा किंटल की चटनी, 6 किंटल की पुड़ी, 10 किंटल की सब्जी और 2 किंटल का हलवा बनाया जाएगा। प्रसादी के रूप में श्रद्धालुओं को टिकड़ चटनी वितरित करेंगे। लगभग 50 हजार श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है।

बेटे की सड़क पर पटककर हत्या करने वाले पिता की लाश मिली कुएं में

बैतुल। बतुल जिले के गाँव सावंगा में पिछले दिनों माँ से मिलने एवं खाना मांगने पर अपने चार वर्षीय बेटे की सड़क पर पटक-पटककर हत्या करने वाले पिता दुर्गाश का शव गांव के ही किसान के खेत के कुएं में पड़ा मिला। कोवाली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम सावंगा में किसान सागर राठौर के खेत के कुएं में गुस्सेवार को दोहात में अज्ञात शव पड़ा नजर आया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला गया। मृतक की शिनाखा गांव के दुर्गाश उर्फ मंगल के रूप में की गई।



पिता ने 4 साल के बेटे को पटककर मारा, शव छोड़कर फरार

मृतक ने बीते 16 जुलाई की रात्रि में अपने चार वर्षीय बेटे कार्तिक की सड़क पर पटककर हत्या कर दी थी और भाग गया था। पुलिस की तीन घंटों उसे हर संभावित स्थान पर तलाश कर रही थी। पुलिस ने आशंका जताई है कि बेटे को सड़क पर पटकने के बाद आरोपित ने यो तो कुर्र में कूदकर आत्महत्या कर ली होगी या फिर नशे की हालत में बह कुर्र में गए और डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने शव को जला अस्पताल पहुंचाया है जहाँ शक़रवार को उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा।

दरअसल दुर्गेश ने महाराज के नासिक निवासी संगीता से प्रेम विवाह किया था। उसकी दो वर्ष की बेटी और चार वर्ष का बेटा है। शराब पीकर पत्नी से आए दिन विवाद करने के कारण वह कुछ दिन पहले बेटी को लेकर मायके चलाई गई थी। बेटे ने माँ के साथ जगह से इंतकार कर दिया इसी कारण से वह पति के पास ही रह रहा था। सोमवार रात्रि करीब 12 बजे दुर्गेश शराब के नशे में घर आया और बेटे ने खाना मांगा तो उसकी पिटाई कर दी। जब वह लौटे तो उसे सड़क पर लाया और पटककर मौत के घाट उतार दिया। सूचना मिलने पर जब 100 की टीम मौके पर पहुंची और अचैत अवस्था में बालक को जिला अस्पताल लाया गया जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया था। कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने के बाद उसकी तलाश शुरू कर दी थी। गुरुवार को उसकी लाश आरोपी में पड़ी मिली।कोतवाली थाना प्रभारी देवकान्ठ डहिया ने बताया कि कुएं में बेटे की हत्या के कारण दुर्गेश की लाश मिली है। आरोहां है कि उसने आत्महत्या कर ली है।

प्राणी मित्र समिति द्वारा पौधारोपण

नरसिंहपुर। एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत प्राणी मित्र समिति द्वारा सतत् पौधारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण पर परिचर्चा आयोजित की जा रही है। इसी के तहत शासकीय अस्पताल के नजदीक पांडे मेडिकोज परिसर में पौधारोपण किया गया कार्यक्रम के मुख्यक अतिथि वरिष्ठ समाज सेवी डी एस त्यागी पांडे मेडिकोज के इंदु खेमरिया प्राणी मित्र समिति के डॉ विनय पटेल, पं.हरि प्रसाद, चन्द्रभान मेहरा, मनीष नामदेव, विनोद सेन आदि द्वारा पौधारोपण कर



संरक्षित किया गया। इस अवसर पर पर्यावरण परिचर्चा में डी एस त्यागी ने बताया कि जलवायु एवं पर्यावरण प्रदूषण एवं विकास के नाम पर अंधाधुंध पेड़ों की कटाई से पर्यावरण अस्तुलित हो गया है। गर्मी का लम्बे समय तक बना रहना स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है। पौधों का रोपड़ ही एक मात्र उपाय है। समिति प्रमुख डा.विनय पटेल ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम के अंतर्गत संस्था द्वारा सतत् पौधारोपण किया जा रहा है। आज संपूर्ण विश्व जलवायु परिवर्तन पर्यावरण संकट के दौर से गुजर रहा है। पर्यावरण संरक्षण के बिना संतुलित समावेशी विकास की कल्पना नहीं की जा सकती अतः हम सभी को सामूहिक रूप से वर्षाकाल में जल का संरक्षण एवं पौधारोपण अधिक से अधिक करना चाहिये इस अवसर पर क्षेत्रीय आमजनों की सहभागिता रही सभी ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। संस्था द्वारा आम, आवंले, गुलमोहर, अशोक, नीम, पीपल, बड़ एवं औषधीय पौधों का रोपण किया जा रहा है।

दो दिवसीय गुरुपूर्णिमा उत्सव

नरसिंहपुर। शासन के निर्देशानुसार समस्त महाविद्यालयों में दिनांक 21 एवं 22 जुलाई 2024 को दो दिवसीय गुरुपूर्णिमा उत्सव मनाया जाना है। इन निर्देशों के तहत इस महाविद्यालय में भी कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। इस कार्यक्रम में प्रथम एवं द्वितीय दिवस में प्रातः 09 से 02:30 बजे तक कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे। कार्यक्रम में विद्यार्थियों द्वारा गुरुजनों का सम्मान किया जावेगा। गुरु पूर्णिमा का महत्व, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर वक्तव्य होगा, गुरु-शिष्य परम्परा भारतीय परंपरा में गुरु-शिष्य संबंधों की महत्ता पर चर्चा, शिक्षा में नैतिकता (नैतिक शिक्षा और वर्तमान शिक्षा प्रणाली में उसकी भूमिका), योग और ध्यान (गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर जोर दिया जायेगा), गुरु के आदर्श- प्रमुख गुरुओं की जीवन गाथा और उनके शिक्षण सिद्धांत, शिक्षा में नवाचार- आधुनिक शिक्षा प्रणाली में नवाचार की भूमिका और उसकी आवश्यकता एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम- विद्यार्थियों द्वारा गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी।

कलेक्टर ने किया होमगाई परिसर में पौधारोपण

नरसिंहपुर। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कलेक्टर श्रीमती शीतला पटेल एवं अपर कलेक्टर श्रीमती अंजली शाह ने डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगाई नरसिंहपुर के परिसर में पौधारोपण किया। उन्होंने यहां अशोक के पौधे रोपे। इस दौरान अशोक के कुल 21 तथा बांस के 60 पौधे रोपे गये। कलेक्टर श्रीमती पटेल ने पर्यावरण संरक्षण के लिए नागरिकों से कहा कि वे अभियान से जुड़ पौधे अवश्य लगाएं। उन्होंने कहा कि धरा को हरा-भरा बनाने और जीवन में पेड़-पौधों के महत्व को समझते हुए पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सभी लोग सहभागिता निभाएं। इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट श्री टीआर चौहान, प्लाटून कमांडर श्री वीरेंद्र सूर्यवंशी, श्री नीरज सिंह ठाकुर, अन्य स्टाफ, होमगाई के जवानों और एसडीआरएफ के जवानों द्वारा भी पौधारोपण किया गया।

कौशल प्रदर्शनी का आयोजन

नरसिंहपुर। विगत दिवस पी.एम.श्री शासकीय महारानी लक्ष्मी बाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नरसिंहपुर में कौशल विकास प्रोत्साहन हेतु कौशल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। जिसमें शासकीय हाई स्कूल नयागाँव की प्राचार्य श्रीमती प्रीति नेमा द्वारा विद्यार्थियों द्वारा बनाये गये मॉडलों का निरीक्षण किया गया।



शासकीय संगीत महाविद्यालय धार में संगीत कार्यशाला में युवाओं ने सीखे गुर

धार। मध्यप्रदेश शासन संस्कृति संचालनालय भोपाल के सौजन्य से गुरु पूर्णिमा पर्व के अवसर पर 15 दिवससीय संगीत कार्यशाला शासकीय संगीत महाविद्यालय धार द्वारा आयोजित की गई। ख्यातिलब्ध संगीत कला गुरु पण्डित विलास खरगोनकर, इंदौर , द्वारा तबला वादन की बारीकियों, तिट, तिरकिट के कायदे,

इसी तारतम्य में 7 दिवसीय चित्रकला कार्यशाला के तहत प्रसिद्ध चित्रकार दुर्गेश बिश्नरे जबलपुर एवं धर्मेन्द्र राठौर, जयपुर द्वारा ललित कला के विद्यार्थियों को रंग कला के विभिन्न आयामों को बताकर मार्गदर्शन प्रदान किया गया। गुरु पूर्णिमा पर्व पर 21 जुलाई को इन्हीं कला गुरुओं और प्रशिक्षित विद्यार्थियों द्वारा संध्याकालीन संगीत

सभा में 4 बजे से सांगीतिक प्रस्तुति होगी एवं प्रातः 11 बजे से व्याख्यान एवं डेमोस्ट्रेशन आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम शासकीय ललित कला महाविद्यालय, घोड़ा चौपाटी धार में रहेगा। इस अवसर पर धार के तमाम सुधि श्रोताओं को सादर आमंत्रित किया गया है। प्रवेश निःशुल्क रहेगा।

साहब अब तो गई नगरपालिका की पूरी जमीन दबंगई के कब्जे में.. पूत के पांव पालने में..



नगरपालिका – सजीव डे राय
नगरपालिका के नाम दर्ज 15/1 जमीन और उस पर निर्मित रहा प्राथमिक बजरिया स्कूल अब बीते दिनों की बात हो गई..! पिछले 90 साल से सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नगरपालिका के नाम लगभग एक एकड़ से ज्यादा 59400 फुट जमीन आने वाले दिनों रामलाल शर्मा स्कूल के कब्जे में दिखाई देगी, इस मूक बजरिया स्कूल की हालत जर जर कहकर नगरपालिका ने उसे पूरे षड्यंत्र के साथ जमींदोज किया है। पाठ्य पुस्तक निगम के अनुदान राशि से निर्मित उस भवन को भी यहां नहीं बक्शा गया रिकॉर्ड में जो सरकारी उम्र

तक पूरी नहीं कर पाई, इस जमीन का चुनाब आडिटोरियम निर्माण के लिए ताबड़तोड़ किया जाना एक तरह नपा की पूरी जमीन हथियाने का षड्यंत्र है। फिर इस पूरे मामले में विधायक का मोन रहना ऐसा प्रतीत कराता है जैसे विधायक तक इस षड्यंत्र में शामिल है..? वर्ष 1972 में शासनाधीन हुई एसएनजी सहित शासकीय नर्मदा महाविद्यालय का रिकार्ड भी इस षड्यंत्र शामिल नजर आ रहा है, ये दोनों संस्था शासनाधीन होने के बावजूद सरकारी रिकॉर्ड में अभी तक दोनों संस्थाओं की जमीन नर्मदा शिक्षा समिति के नाम पर दर्ज चल रही है, फिर नर्मदा शिक्षा संस्था सालाना

विजिट पर इन्हें अपना बताकर उसका लाभ उठा रही। वर्तमान की दो फोटो देखकर इसकी सच्चाई स्वतं सामने आती है। जिसमें नर्मदा शिक्षा समिति ने एस एन जी स्कूल से स्टेडियम जाने वाले मार्ग पर अतिक्रमण कर उसे न केवल बंद कर दिया, उस मार्ग पर तीन माला भवन बना लिया और जिसके सामने टूटी हुई मूक बजरिया स्कूल के बच्चे अब सड़क पर बैठकर विद्याध्ययन करने को मजबूर हो गए तो दूसरी तरफ तोड़ी हुई इस मूक बजरिया स्कूल के खाली रकबे का उपयोग एनई एस में लगाई जा रही शिक्षाविद पंडित रामलाल शर्मा के स्कूली बच्चों की प्रार्थना होने लगी है।

गोड़ीखेरी रैयत निवासी आदिवासी ने कहा भूमि पर कर रहे हैं जबरन कब्जा, रात 10 बजे किया सीमांकन

हीरालाल गोलानी सोहागपुर
विगत मंगलवार को जनसुनवाई में करीबन चार आवेदन प्रशासन को प्राप्त हुए। इस अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी बृजेंद्र रावत, तहसीलदार अल्का एक्का, जनपद पंचायत सीईओ श्री अग्रवाल आदि उपस्थित थे।

रोचक आवेदन – जनसुनवाई में एक आवेदन बहुत ही रोचक है। जिसमें आवेदन ने लिखा है मेरी भूमि पर कब्जा करने की धौंस देकर कहते हैं कि हम केस जीत गए हैं। हम मुझे प्राप्त हो चुकी है। बाद में मैंने खेत पर एक नलकूप खुदवाया था। इसी भूमि पर कृषि करते अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। लेकिन तीन व्यक्तियों रामदीन पिता सुखलाल निवासी नया पट्टन, रंगीलाल पिता सुरेश, अशोक पिता सुरेश निवासी कूकरा ने जबन हमारी कृषि भूमि पर कब्जा करने को तैयार हैं। हमसे कहते हैं कि हम केस जीत गए हैं। तेरी जमीन पर पटवारी और तहसीलदार से मिलकर कब्जा कर लेंगे। मुझे न्यायालय का कोई भी नोटिस प्राप्त नहीं



हुआ न ही कोई किसी कागज पर कोई हस्ताक्षर किया है मैं ड्यूटी पर था। मुझे दूसरे दिन जानकारी प्राप्त हुई कि आर आई और पटवारी जिनके नाम नहीं जानता के द्वारा रात के 10 बजे सीमांकन किया गया है। यह सब अनावेदकगणों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है। अब उनके द्वारा धमकी दी जा रही है। तुम जमीन खाली करके यहां से भाग जाओ, नहीं तो हम तुझे परिवार सहित जान से खत्म कर देंगे। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं धमकी से भयबोधित हूँ। आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरी उपस्थिति मेरी भूमि का सीमांकन कराया जाए। जिससे उक्त भूमि की स्थिति स्पष्ट हो सके।

प्रशासन से आग्रह – इस संबंध में

आवेदक ने बताया कि मैं वन विभाग भैरों सुखतवा केसला में काम करता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि रात को दस बजे कैसे सीमांकन हुआ। हम पढ़े लिखे नहीं हैं। घर पर बाल बच्चे एवं पिताजी रहते हैं। मैं फिर नौकरी पर चला जाऊंगा। प्रशासन से आग्रह है कि हमारा सीमांकन जल्दी कर दें। फिर वन विभाग की नौकरी में चला जाऊंगा। मेरा परिवार परेशान न हो।

नहीं मिला प्रधानमंत्री आवास का पैसा – अम्बेडकर वाई निवासी शेख अनवर ने आवेदन दिया है कि मैंने पहले भी जनसुनवाई में आवेदन दिया था। कि मुझे प्रधानमंत्री आवास का पैसों की किश्त नहीं मिली जा रही है।

भूमि पर कब्जा हटवाएं – ग्राम

आमदेही के बालकृष्ण कुशवाहा पिता रामसिंह कुशवाहा निवासी ने आवेदन देकर खसरा नंबर 100 रकबा 2.19 हेक्टेयर एवं नहर भूमि पर भगवान दास मेहरा के द्वारा कब्जा कर लिया है। हमें कृषि कार्य करने के लिए रास्ता देने निवेदन किया है।

उल्लेखनीय – जनसुनवाई में अधिकांश आवेदन पत्रों पर यदि स्थानीय प्रशासन सकारात्मक कदम उठाए तो ऐसे आवेदन- पत्र बार बार न आएँ। जनसुनवाई में प्रदान किए आदिवासी इमारत के आरोप में सत्यता है तो यह गंभीर मामला है कि आर आई पटवारी ने रात के दस बजे सीमांकन किया है। ऐसे मामले में कलेक्टर सोनिया मीना को संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए।

कलेक्टर की अध्यक्षता में नेशनल अचीवमेंट सर्वे जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक संपन्न

नरसिंहपुर। कलेक्टर श्रीमती शीतला पटेल की अध्यक्षता व सीईओ जिला पंचायत श्री दलीप कुमार की मौजूदगी में जिले में नेशनल अचीवमेंट सर्वे के सफल क्रियान्वयन हेतु गठित टास्क फोर्स की जिला स्तरीय बैठक डाइट सभागार में शुक्रवार को आयोजित की गई। कलेक्टर श्रीमती पटेल ने जिले के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में नेशनल अचीवमेंट सर्वे के तैयारियों को लेकर गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष और अच्छे प्रयास करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार उनके बुनियादी ज्ञान एवं समझ को विकसित करने के लिए सतत मॉनीटरिंग करें। विद्यार्थी अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें इसके लिए विद्यालय में बच्चों को नवाचार के साथ शिक्षण कार्य करायें। कलेक्टर ने कहा कि शासकीय व अशासकीय विद्यालय में कोई अंतर नहीं होता है। अशासकीय विद्यालयों की मॉनीटरिंग के लिए रणनीति तैयार कर नोडल अधिकारी नियुक्त कर रैडम आधार पर सतत मॉनीटरिंग कर बच्चों के स्तर को जांचा जाये। विद्यार्थियों के स्तर को बढ़ाने के लिए



अकादमिक स्तर पर टीम तैयार करें। कठिन बिंदुओं का निराकरण कर छात्र के ज्ञान स्तर को बढ़ायें और लक्ष्य हासिल कर सकें। बैठक में कलेक्टर श्रीमती पटेल ने कहा कि सर्वे के दौरान विद्यालयों में ओएमआर सीट पर ली जाने वाली परीक्षा के फॉर्मेट एवं विश्लेषण के सवाल पर डिस्ट्रिक्ट को- ऑर्डिनेटर से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि प्रश्न बैंक एवं क्विजों से प्रश्नों को तैयार कर विद्यार्थियों को इन प्रश्नों का अभ्यास करवायें। सीईओ जिला पंचायत श्री दलीप कुमार ने नेशनल अचीवमेंट सर्वे के कलेंडर एवं टूल के आधार पर विद्यालय में गतिविधियां करवायें। प्रश्नों के उत्तर प्रभारी और अन्य अधिकारी ने कर्मचारी मौजूद थे।

की जाये और उनकी दक्षता हासिल करने के प्रयास किये जायें। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी श्री अनिल व्योहार, जिला परियोजना समन्वयक डॉ. आरपी चतुर्वेदी, डाइट प्राचार्य श्री एमए खान, डाइट व्याख्याता श्री जीएल उर्गेलिया, सहायक प्राध्यापक डाइट श्री आरके यादव के द्वारा नेशनल अचीवमेंट सर्वे की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान सहायक संचालक शिक्षा श्री एसएस मसराम, जिला स्तरीय गठित नेस टास्क फोर्स समिति के सदस्य, समस्त विकासखंड के विषयवार सपोट एवं प्रशिक्षण जिला स्तर- डाइट, विषयवार सपोट एवं प्रशिक्षण जिला स्तर- डीआरजी, ब्लाक नेस प्रभारी और अन्य अधिकारी ने कर्मचारी मौजूद थे।

